



सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा



श्री 1008 महामंडलेष्ट्र
श्री स्वामी रामानंद
दासजी महाराज
श्री रामानंद दास अन्नक्षेत्र सेवा
ट्रस्ट, तपोवन आश्रम
स्व. पं. पू. 1008 श्री रामानंद जी
तपोवन मंदिर, मोच गाँव, सुलत

वर्ष-12 अंक:47 ता. 09 अगस्त 2023, बुधवार, कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com



/Suratbhumi.com



/Suratbhumi



/Suratbhumi



/Suratbhumi



/Suratbhumi

अरविंद केजरीवाल पर ही बरसने लगे कांग्रेस नेता, बोले- झगड़े में ना पड़ते तो बिल भी ना आता



नई दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल पर संसद के अंदर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का जमकर साथ दिया। हालांकि सोमवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी 131-103 से पास हो गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पहले से ही पार्टी लाइन से हटकर इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वह ताकत को लेकर केंद्र के साथ झगड़े में ना पड़ते तो यह बिल भी ना आता। सोमवार को बिल पास होने के बाद एक वीडियो संदेश जारी करके संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ झगड़े में ना पड़े होते तो सरकार इस तरह का बिल कभी ना लाती। एक समय था जब दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार का आपसी नियंत्रण होता था। सबकुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में अरविंद केजरीवाल आए और राजनीति शुरू कर दी। वह केंद्र के साथ ताकत के झगड़े में पड़ गए और लोगों के हित को भूल गए। इसलिए केंद्र यह बिल लेकर आया है। नहीं तो दिल्ली के लिए इस तरह के बिल को कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए काम करने की बजाय दिल्ली की सरकार राजनीति ज्यादा कर रही है। अब मुझे यही उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शहर के विकास के लिए काम करेंगे। हालांकि अभी वह बिल पास होने के बाद और भी ज्यादा राजनीतिक बयान देंगे। बता दें कि राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले भी संदीप दीक्षित ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी समेत दृष्टिगत गठबंधन ने संसद में इस बिल का विरोध किया। वहीं केंद्र सरकार ने वाइसआर कांग्रेस और बीजेपी की मदद से राज्यसभा में यह बिल भी पास करवा लिया। लोकसभा में बीते सप्ताह इस बिल को पारित किया गया था। वह दिल्ली की सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर आए गए अत्यादेश की जगह लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार अत्यादेश लेकर आई थी।

राघव चड्ढा की बढ़ सकती है मुश्किल, बिना सहमति सांसदों के नाम डालने पर धिरे; शाह बोले- संसद में भी फर्जीवाड़ा

● अमित शाह राज्यसभा में वोटिंग के दौरान ही भड़क गए और कहा कि यह तो दिल्ली की बात ही नहीं है। अब तो सदन में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने जांच की सिफारिश की।

नई दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में हार का मुंह देखा पड़ा। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत INDIA गठबंधन का हिस्सा बने दलों का समर्थन हासिल करने के बाद भी उसे झटका लगा है। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी एक विवाद में जुड़ गया है। दरअसल उन्होंने बिल को पेश किए जाने के बाद उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा था। उनका प्रस्ताव तो गिर ही गया। इसके साथ ही उन्होंने जिस सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा था, उसमें शामिल 5 सांसदों ने उन पर आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना ही उनके नाम लिख दिए गए।

सनक याद रहेगी... बीमार मनमोहन को लाने पर भड़की बीजेपी क्या बोली कांग्रेस
इस पर अमित शाह राज्यसभा में वोटिंग के दौरान ही भड़क गए और कहा कि यह तो दिल्ली की बात ही नहीं है। अब तो सदन में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष जांच के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर राघव चड्ढा ने कहा कि यदि उन्हें विशेषाधिकार समिति नोटिस



भेजती है तो वह जवाब देंगे। चड्ढा का बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया था। सेलेक्ट कमेटी में बिना मंजूरी के ही नाम शामिल किए जाने का आरोप जिन सांसदों ने

लगाया है, उनमें एस. फैगॉंग कोन्याक, नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा और एम. थंबोदुरई शामिल हैं।

समीक्षादनल में आप को मिला हार का

गम, कांग्रेस नेता ने ही 'पीट दी ताली'

इन लोगों ने डिप्टी स्पीकर से शिकायत की थी कि बिना उनकी अनुमति के ही सेलेक्ट कमेटी में उनके नामों को शामिल किया गया है। प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी के नाम जैसे ही डिप्टी स्पीकर पढ़ने लगे तो अमित शाह ने कहा कि इनमें से 5 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से ही इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तो जांच होनी चाहिए। शाह ने कहा कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। अमित शाह ने कहा कि इन सांसदों के स्थान पर किसने साइन कर दिए, यह जांच का विषय है। वहीं वाइसआर कांग्रेस के नेता वी. साई रेड्डी ने भी कहा कि उनकी पार्टी के भी एक लीडर का नाम बिना सहमति के ही शामिल कर लिया गया।

बनने से पहले ही बिखरने लगा विपक्ष का INDIA, TMC के खिलाफ ताल ठोकेंगे CPM

इस बीच केंद्रीय मंत्री हरीद्वीप पुरी ने कहा कि मैं 6 साल से मंत्री हूँ और 40 सालों से संसद की कार्यवाही देख रहा हूँ। इस तरह का फर्जीवाड़ा तो आज तक सामने नहीं आया। इस मामले की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गौहिल ने चड्ढा का बचाव किया है। उन्होंने

इस पर अमित शाह राज्यसभा में वोटिंग के दौरान ही भड़क गए और कहा कि यह तो दिल्ली की बात ही नहीं है। अब तो सदन में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष जांच के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर राघव चड्ढा ने कहा कि यदि उन्हें विशेषाधिकार समिति नोटिस भेजती है तो वह जवाब देंगे। चड्ढा का बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया था। सेलेक्ट कमेटी में बिना मंजूरी के ही नाम शामिल किए जाने का आरोप जिन सांसदों ने लगाया है,

कहा, 'यह नियम है कि यदि मैं कोई संशोधन प्रस्ताव ला रहा हूँ तो फिर सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव दे सकता हूँ। इसके लिए मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वह अपना नाम वापस ले सकता है। इसके लिए सदस्यों के साइन लेने की कोई बाध्यता नहीं होती।'

अधिक समय तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों पर होगी सख्ती से होगी कार्रवाई-गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

श्री गहलोत सोमवार रात मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था को समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मनचलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश



दिए। गहलोत ने कहा कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड संभारित किया जाए तथा चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा की घटना दुःख है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि इस घटना को राजनीतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे हैं जो कि उचित नहीं है।

पीसीएस ज्योति मौर्य से कैमरे के सामने होगी पूछताछ, पति आलोक ने हर महीने 5 लाख कमाई का लगाया है आरोप

लखनऊ। पति आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच तेज हो गई है। जांच टीम अब ज्योति से पूछताछ की तैयारी में है। ज्योति से उनकी प्रॉपर्टी, गाड़ी और बैंक खातों की जानकारी भी मांगी गई है। बताया जा रहा है कि ज्योति से पूछताछ कैमरे के सामने की जाएगी। पीसीएस बन जाने के बाद होमागड कमांडेंट से अफेयर और पति को तलाक देने की कोशिश को लेकर चर्चा में आई ज्योति मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पति आलोक मौर्य ने ज्योति पर ऊपरी कमाई का आरोप लगाया था जिसकी जांच कर रही टीम ने अब नोटिस जारी कर ज्योति की सम्पत्ति का पूरा ब्योरा मांग है।

था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अलग-अलग तरीकों से अवैध लेनदेन किए हैं। ऐसे अर्जित किए गए धन को कई सेक्टरों में निवेश किया गया है। कई मकान, प्लॉट और फ्लैट लिए गए हैं।



आलोक ने अपने आरोपों के सपोर्ट में कई सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने एक डायरी के कुछ पन्ने भी अपनी सज्जह देनी होगी। इसके बाद कमेटी ज्योति के लेनदेन का उल्लेख है। मिली जानकारी के अनुसार अब जांच कमेटी ज्योति मौर्य को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने वाली है। ज्योति 2019 से 2021 के बीच कौशांबी में तैनात रही हैं। बताया जा रहा है कि आलोक ने

जिस डायरी के पन्ने सामने रखे हैं वो इसी दौरान की है। आरोप है कि डायरी में ज्योति के अवैध लेन-देन का हिसाब है। इसे लेकर एक महीने में पांच लाख रुपए से अधिक की कमाई की जानकारी का दावा किया गया है।

आलोक का भी बयान लेगी जांच टीम
ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच कमेटी ज्योति से पूछताछ के अलावा उनके पति आलोक मौर्य का भी बयान लेगी। चर्चा है कि आलोक ने जांच कमेटी को जो दस्तावेज सौंपे हैं उनमें 33 करोड़ से अधिक लेनदेन का ब्योरा है। जांच कमेटी के अध्यक्ष ने पिछले दिनों बताया था कि आरोप लगाने वाले को प्रमाणपत्र देना होगा। इसी तरह आरोपित पक्ष को भी अपनी सज्जह देनी होगी। इसके बाद कमेटी अपना निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आचरण नियमावली ही जांच का केंद्र है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जांच जब पूरी हो जाएगी तो इसकी जानकारी अफसरों को दी जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर में अभी और सताएगी उमस, 2 दिन तेज बारिश के आसार कम

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अगले दो-तीन दिन तक अच्छी बारिश की संभावना कम है। इस कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाप रहेगे और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह से ही सूर्य के तेवर तल्लख दिखे। हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रही। इसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफेददर्जन में सोमवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री

सेल्सियस रहा। यहां पर आद्रता 79 से 61 फीसदी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। इस्का-दुस्का इलाकों में ही छिटपुट



बारिश की संभावना है। इसके चलते तापमान में भी इजाफा होगा और उमस भी बनी रहेगी। दिल्ली में 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 102 दर्ज किया गया। वहीं पड़ोसी उत्तर प्रदेश के

गाजियाबाद में एक्यूआई 102, ग्रेटर नोएडा में 127 और नोएडा में 120 रहा जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में यह 121 दर्ज किया गया। बता दें कि, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच

● मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाप रहेगे और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह से ही सूर्य के तेवर तल्लख दिखे।

'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

दिल्ली में वाहन मालिक हो जाएं सावधान, अब खाली प्लॉट से भी उठाए जा रहें पुरानी गाड़ियां

नई दिल्ली। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास भी 10 से 15 साल पुरानी कार और बाइक हैं तो अब सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग की टीमों ने ऐसे वाहनों को घरों के बाहर से उतारने का अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को अब तेजी से हटाया जा रहा है। परिवहन विभाग के निर्देश पर इन वाहनों को जब्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों में गलत तरीके से वाहनों को जब्त करने की भी शिकायतें बढ़ रही हैं। बाहरी दिल्ली में ज्यादा समस्या है, जहां खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों को भी उतारा जा रहा है। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंटेशन ने विरोध जताया है। स्कूल एकता ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंटेशन के अध्यक्ष रामचंद्र का कहना है कि रोहिणी में उनके एक परिचित की गाड़ी को



खाली प्लॉट से उतारा गया। उनका घर प्लॉट के बगल में ही था। जब मौके पर विरोध किया तो परिवहन विभाग की इंफोसमेंट यूनिट के लोग गाड़ी छोड़कर चले गए। वहीं, रोहिणी निवासी रविंद्र का कहना है कि उनकी एक गाड़ी 10 वर्ष पुराने है, जिसमें सिंचु बांडर

के नजदीक अपने भाई के प्लॉट में खड़ी किया था। वहां परिवहन विभाग और एजेंसी के लोग पहुंचे और गाड़ी को क्रोन से उतारकर ले जाने लगे। विरोध किया तो गाड़ी छोड़कर चले गए। परिवहन मंत्री का कहना है कि किसी के घर में अगर पुराना वाहन खड़ा है तो उसे नहीं उतारा

जाएगा तो ऐसे में प्लॉट में खड़े वाहनों को भी नहीं उतारा जाना चाहिए।

57 लाख वाहनों की मियाद खत्म
दिल्ली-एनसीआर में एनजीटी ने जुलाई 2016 में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 2021 के बाद से दिल्ली का परिवहन विभाग अवधि पूरी कर चुके वाहनों को तेजी से हटा रहा है। हर महीने उन वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त किया जा रहा है, जो इस अवधि को पूरा कर चुके हैं। राजधानी में करीब 57 लाख वाहन अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि अवधि पूरी कर चुके वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर सख्ती से कार्रवाई न की जाए तो इन वाहनों को निकालना मुश्किल हो जाएगा।

हारकर भी इस लड़ाई से क्या हासिल कर पाए अरविन्द केजरीवाल, आगे हो सकता है फायदा

नई दिल्ली। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी आसानी से पास हो गया। बिल के समर्थन में 131 सांसदों ने वोट किया तो विपक्ष में 102 मत पड़े। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत 26 दलों के विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने इस बिल को राज्यसभा में रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंकगणित में पिछड़ गए। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी लड़ाई को 2024 का समीक्षादनल तक करार दिया

था। इसमें हार के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी ने भाजपा को चार बार हराया और अब उन्होंने चोर दरवाजे से सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। बिल पास होने का क्या असर-लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद अब यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही दिल्ली में सेवा पर केंद्र सरकार के अधिकार को कानूनी संरक्षण हासिल हो जाएगा। हालांकि, कानून का दिल्ली सरकार पर कोई नया असर नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो प्रावधान केंद्र सरकार ने किए हैं

वह अत्यादेश के साथ ही लागू हो गए थे। इसके मुताबिक, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला नेशनल कैपिटल स्विबल सर्विस अथॉरिटी के जरिए होगा। अथॉरिटी में सीएम, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह सदस्य होंगे। बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाएंगे और विवाद की स्थिति में एलजी का फैसला अंतिम होगा। दिल्ली सरकार इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दे चुकी है। अब उसकी सारी उम्मीद न्यायापालिका पर टिकी है।

हारकर भी क्या हासिल कर पाए केजरीवाल-आप
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही इस मुकामले में हार गए हैं, लेकिन जिस रणनीति से उन्होंने यह लड़ाई लड़ी उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर पाए हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि जिन विपक्षी दलों से कभी उनका कट्टर विरोध था, उनको भी साथ लाने में कामयाब रहे। संविधान की दुहाई देकर वह कांग्रेस समेत अन्य दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। यही वजह है कि 10 राज्यसभा सांसदों वाली पार्टी राज्यसभा में 102 वोट हासिल कर पाई। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी

केजरीवाल का साथ देने में हिचक रही थी लेकिन विपक्षी एकता के लिए बिल के विरोध को शर्त बनाकर 'आप' ने हथ थामने पर मजबूर किया। विपक्षी टीम में शामिल होने से अगले लोकसभा चुनाव में आप को फायदा होने की उम्मीद है। हाल ही में आए एक सर्वे में भी इसकी भविष्यवाणी की गई है। पिछले हफ्ते ही इंडिया टीवी के सर्वे में कहा गया है कि अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में आप को 10 सीटें हासिल हो सकती हैं। दिल्ली में भी पहली बार उसका खाता खुल सकता है। 2019

के लोकसभा चुनाव में आप को महज पांच सीटें पर जीत मिली थी। इस बार दिल्ली में दो और पंजाब में 8 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। खूद को पौडित दिखा सहानुभूति बटोर सकती है पार्टी-कहते हैं कि राजनीति असल में परसेप्शन का खेल है और आप ने इसमें अच्छे कुशलता हासिल की है। पिछले कई सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि केंद्र की मोदी सरकार उन्हें कामकाज करने से रोक रही है और बाधाओं से लड़ते हुए वह काम कर रहे हैं। सेवा विधेयक पास होने के बाद एक

बार फिर केजरीवाल को अपनी बात को बल देने का मौका मिलेगा। संकेत उन्होंने विधेयक पास होने के तुरंत बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में भी दे दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने चोर दरवाजे से सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी को देश सभालने का काम दिया था लेकिन वह दिल्ली में चपरासियों का भी ट्रांसफर-पोस्टिंग करना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो आप इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और जनता के बीच जाकर प्रचारित करने की तैयारी में जुटी है।

ग्रामीणों ने दी धमकी, नदी पर स्थायी पुल नहीं बना तो वोट भी नहीं देंगे

इंदौर। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के ग्रामीणों ने सरकार को धमकी दी है कि यदि उनके गांव में नदी पर पुल नहीं बना तो आगामी चुनावों में वे किसी को भी वोट नहीं देंगे। इस तरह से यहां तीन गांवों के लोगों ने मिलकर धमकी दी है कि अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। बताया जा रहा है कि तीनों गांव वालों की 2014 से यह प्रमुख मांग है। जो तीन गांव शामिल हैं उनमें से हैं, राइम मोको, पिडी राइम और टोडी राइम। यहां की आबादी लगभग 400 है और उनमें से लगभग 300 मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या केवल 13.84 लाख है। जानकारी के अनुसार यहां पर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने एक अस्थायी पुल बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ लकड़ी की रेलिंग के साथ यह 20 मीटर लंबा है। यह लकड़ी का पुल रोजाना के लिए तो ठीक है लेकिन यह मानसून के दौरान उपयोगी नहीं है क्योंकि यह पिसम नदी की सहायक नदी हिजम के जल स्तर से नीचे चला जाता है। राइम मोको गांव में रहने वाले पोकेप राइम ने कहा कि जब नदी उठान पर होती है, तो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। उन्हें डर है कि बच्चे लॉग ब्रिज से फिसल सकते हैं। उचित पुल के अभाव में, गांव मानसून हो या न हो, किसी मरीज को अस्पताल ले जाना बेहद मुश्किल होता है। पोकेप ने कहा कि हमें मरीजों को अपनी पीठ पर लाकर नदी पर बने लॉग ब्रिज को पार करके निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आलो जनरल अस्पताल ले जाना पड़ता है। गांवों के लोगों का मानना है कि सड़क संघर्ष को मुद्दा क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित कर रहा है। रीम मोको, पिडी रीम और टोडी रीम गांवों के निवासियों ने हाल ही में इस मुद्दे पर आपस में चर्चा कर राज्य सरकार से नदी पर एक स्थायी पुल बनाने की मांग की है।

34 साल पुराने कश्मीरी हिंदू नरसंहार केस को फिर से खोलने की तैयारी

नई दिल्ली। कश्मीरी हिंदू नरसंहार मामले में 34 साल पहले के एक केस को खोलने की तैयारी हो रही है। यह केस रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू के मर्डर से जुड़ा है, जिसके पीछे यासीन मलिक के साथियों का हाथ बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 34 साल बाद 1989-90 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार के मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। पहला केस रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू के मर्डर से जुड़ा है, जिनकी हत्या यासीन मलिक के जेकेएनएफ आतंकवादियों ने 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में कर दी थी। जज गंजू ने ही जेकेएनएफ आतंकी मकबूल बट को फांसी की सजा सुनाई थी। ये सजा ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक रवींद्र महारात्रे की हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद दी गई थी। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए, जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने एक विज्ञापित जारी कर इस हत्याकांड के तथ्यों या परिस्थितियों से परिचित सभी लोगों से आगे आने और उसकी जानकारी साझा करने की अपील की है। गौरतलब है कि जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में गंजू ने अगस्त 1968 में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक और नेता मकबूल बट को 1966 में पुलिस इन्स्पेक्टर अमर चंद की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी। सेवानिवृत्ति के बाद 67 वर्षीय गंजू की 4 नवंबर, 1989 को श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जज गंजू द्वारा 1968 में दिए गए भट की सजा को 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद 1984 में भट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। एसआईए ने यह भी कहा है कि सामने आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान छिपाकर रखी जाएगी।

पति को बार-बार काला कहकर अपमानित करना भी तलाक का आधार : हाईकोर्ट

बेंगलुरु। पत्नी द्वारा अपने पति को बार-बार काला कहकर अपमानित करना भी तलाक का आधार बनता है, इस आशय के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पति की रिश्ता का रंग काला होने के कारण उसका अपमान करना क्रूरता है। ऐसा यदि लगातार जारी रहता है तो फिर यह तलाक का एक ठोस आधार बनता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक के एक केस की सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 41 वर्षीय पत्नी से तलाक दिए जाने की मंजूरी देते हुए हाल में एक फैसले में यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी काला रंग होने की वजह से अपने पति का अपमान करती थी और वह इसी वजह से पति को छोड़कर चली गई थी। उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत तलाक की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि इस पहलू को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने पति के खिलाफ अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए। कोर्ट ने कहा कि ये तथ्य निश्चित तौर पर क्रूरता के समान हैं। बेंगलुरु के रहने वाले इस दंपति ने 2007 में शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। पति ने 2012 में बेंगलुरु की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। महिला ने भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत अपने पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था। उसने घरेलू हिंसा कानून के तहत भी एक मामला दर्ज कराया और बच्ची को छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। जबकि उपलब्ध साक्ष्य यह साबित करते हैं कि उसे पति का रंग काला होने की वजह से इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से उसकी तलाक का आधार बनता है।

टली होकर लड़की ने किया सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिसवालों को सुनाई गालियां

बेंगलुरु। अपनी रईसी के मद में चूर एक लड़की ने टली होकर सड़क पर जमकर ड्रामा किया। इतना ही नहीं उसने पुलिसवालों को भी जमकर गालियां दीं। लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह नजारा आईटी सिटी बेंगलुरु की सड़क पर उस समय दिखाई दिया जब एक लड़की ने शराब के नशे में चूर होकर पुलिस को खूब गालियां दीं। इतना ही नहीं उसने आते जाते लोगों को भी नहीं बख्शा और उनको भी नशे में खूब गालियां दीं। उसकी गालियां सुनते हुए पुलिस के अधिकारी किसी तरह से उसको दूसरी महिला की मदद से घर तक ले जाने का प्रयास करते रहे। जबकि वह घर जाने को तैयार नहीं थी। लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती बेंगलुरु की चर्च स्ट्रीट पर पुलिस अधिकारियों को गालियां देती हुई देखी जा सकती है। लड़की पुलिस वालों की शर्म ना करते हुए उनको जी भर-भरकर गालियां देती हुई नजर आ रही है। बाजूजुड़ इसके पुलिसकर्मी शांत होकर उसकी गालियां सुनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्को घर छोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस पूरे ड्रामे को किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया जोकि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया है। लड़की पुलिसवालों के साथ-साथ यहां से गुजरने वाले हर किसी राहगीर को खूब गालियां दे रही है। इस दौरान पुलिस ने लड़की को घर तक ले जाने के लिए दूसरी महिला की मदद ली। नशे में धुत लड़की ने बार-बार महिला के साथ भी धक्का-मुक्की की और आंटी रिशवा में बैठने से मना करती रही। कर्नाटक के बेंगलुरु में चर्च स्ट्रीट क्षेत्र के पास हुए इस वाक्ये से साफ नजर आया कि इस परि्या में बहुत सारे पब, बार और रेस्तरां मौजूद हैं। पता चला है कि नशे में मस्कीश लड़की ने अपनी गाड़ी को वहां नो पार्किंग जॉन में ही पार्क कर दिया था। इसी बात को लेकर लड़की और टैफिक पुलिस के बीच बहस हुई। इसके बाद लड़की ने पुलिसकर्मीयों को गालियां देना शुरू कर दिया। एक पुलिसकर्मी का कॉलर तक पकड़ लिया। हालांकि मामलों को देखकर स्पष्ट हो गया था कि युवती के खिलाफ पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

पुणे में ओमीक्रॉन का नया वैरिएंट मिलने से महाराष्ट्र में फिर से बढ़ रहा कोरोना का खतरा

मुंबई। जहां दुनिया कोरोना महामारी से उबर रही है, वहीं एक बार फिर कोरोना के नए खतरनाक वैरिएंट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में अब ओमीक्रॉन के नए सब-वैरिएंट ने टैंगन बढ़ा दी है। वहीं यह बात सामने आई है कि मई महीने में ही पुणे में एक मरीज मिला था। इंजी.5.1 को मई महीने में महाराष्ट्र में पाया गया था। इसके निदान के दो महीने हो गए हैं और इसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। जून और जुलाई में राज्य में इस सबवैरिएंट के प्रभाव में वृद्धि नहीं देखी गई। जबकि, वर्तमान में राज्य एक्सबी.1.16 और एक्सबी.1.2.3 वैरिएंट का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सक्रिय कोविड-19 रोगियों की संख्या जुलाई के अंत में 70 से बढ़कर 6 अगस्त को 115 हो गई।

भारत जोड़ो यात्रा : गुजरात से शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, मेघालय में होगा खत्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक चलने वाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 'नवंबर से पहले' गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के पामीघाट तक मार्च की संभावना जताई थी। हालांकि, मार्ग और तारीखों के बारे में विवरण अभी तक अपुष्ट है। मंगलवार को खबर की पुष्टि करते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के भीतर पार्टी के नेता एक समानांतर मार्च करेंगे। प्रमुख कांग्रेस नेता पश्चिमी राज्य के विभिन्न हिस्सों में मार्च का नतुल करेंगे।

गुजरात से मेघालय होगी यात्रा

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले कहा, 'राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से मेघालय तक शुरू होगा।' इससे पहले सोमवार को, गुजरात कांग्रेस ने कहा कि उसने नए बहाल सांसद को 'महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि' से अपनी यात्रा शुरू करने का निर्मंत्रण दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमित चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश से होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई राज्य इकाइयों ने पदयात्रा के दूसरे चरण के लिए इसी तरह के या अन्य सुझाव दिये हैं।



पहला चरण सफल रहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से 4,000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा शुरू की थी और जनवरी के अंत में श्रीनगर में समाप्त हुई थी। जिसका लाभ पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिला। राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार, यात्रा ने निरस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा से मुकाबला करने और दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए नई ऊर्जा दी है और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनावों और उससे पहले राज्य चुनावों में लाभ उठाने की दृष्टि से, कांग्रेस नेता अब अपनी दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि पैदल मार्च का पहला चरण जो पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ और 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के बाद 130 दिनों से अधिक समय बाद कश्मीर में समाप्त हुआ, बेहद सफल रहा।

पीएम मोदी का मौन व्रत तोड़ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया : कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की है। भाजपा की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, पीएम मोदी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लगे? तीसरा सवाल पीएम मोदी ने आज तक मणिपुर के सीएम को खर्खास्त क्यों नहीं किया?



कांग्रेस सांसद गोरोई ने कहा हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं। यह कभी भी संख्या के बारे में नहीं था बल्कि मणिपुर के लिए न्याय के बारे में था। मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सदन सरकार में अविश्वास व्यक्त करता है। इंडिया मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लाया है। मणिपुर न्याय चाहता है। लोकसभा में गोरोई ने कहा प्रधानमंत्री ने संसद में न बोलने का मौन व्रत ले लिया है। इसकारण उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। गोरोई ने कहा प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार, मणिपुर में उनकी सरकार विफल हो गई है। इसकारण, मणिपुर में 150 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 5000 घर जला दिए गए, लगभग 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं और लगभग 6500 एकआईआर दर्ज की गई हैं। राज्य के सीएम, जिन्हें बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे का समय निर्धारित है। सांसदों की संख्या के आधार पर सभी राजनीतिक दलों को सदन में बोलने का समय अलॉट कर दिया गया है। हालांकि जम्मू तक पड़ने पर स्पीकर या पीठासीन सभापति इस समय को बंद कर सकते हैं। लोक सभा में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 301 सांसद हैं, इसकारण भाजपा को भाषण देने के लिए लगभग 5000 घर जला दिए गए, लगभग 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं और लगभग 6500 एकआईआर दर्ज की गई हैं। राज्य के सीएम, जिन्हें बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना

राजनीतिक दलों की बात करें तो 23 सांसदों वाले टीएमसी को 29 मिनट, 22 सांसदों वाली वार्डएसपी को कांग्रेस को 29 मिनट, शिवसेना को 23 मिनट, जेडीयू को 21 मिनट, बीजेपी को 16 मिनट, बसपा को 12 मिनट, एलजेएसपी को 8 मिनट का समय अलॉट किया गया है। एआईएडीएमके, अपना दल, आजसू, एएमएनएफ, एस्केएम, एनडीपीपी, एनपीपी, एपीएफ और निर्दलीयों को मिलाकर 17 मिनट का समय अलॉट किया गया है। इसके अलावा एनसीपी, सपा, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, नेशनल काॅंग्रेस, जेडीएस, जेएमएम, अकाली दल और आर संहित अन्य सभी बचे हुए दलों को कुल मिलाकर 52 मिनट का समय अलॉट किया गया है।

भाजपा नेता किरौट सोमैया का ठाकरे गुट पर 100 करोड़ के कोविड घोटाले का आरोप

मुंबई (एजेंसी)। भाजपा नेता किरौट सोमैया एक बार फिर सियासी मैदान में वापसी करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले किरौट सोमैया का कविट आपतिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे वे संकट में पड़ गये। इस मामले की जांच चल रही है। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने किसी घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब फिर किरौट सोमैया ने वित्तीय घोटालों को सामने लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब किरौट सोमैया ने ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया है। किरौट सोमैया ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर कोरोना काल के दौरान मुलुंड के कोविड सेंटर में 100 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा किरौट सोमैया ने वट्टी किरौट है। इन्होंने उन्होंने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार की कंपनी रिचर्डसन क्रूज से मुलुंड में साइट पर कब्जा कर लिया। सिडको को अस्थायी अस्पताल बनाने का आदेश

दिया गया। सिडको ने 1850 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए ओक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को नियुक्त किया। ओक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी एक इन्वेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। अस्पताल को 7 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2022 तक 25 महीने के लिए खुला रखा गया था। इसके लिए किरौट के तौर पर ओक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को 90 करोड़ रुपये दिए गए। किरौट सोमैया ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने निर्माण के लिए 10 करोड़ देकर 100 करोड़ का घोटाला किया है। किरौट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया है कि रिचर्डसन कंस्ट्रक्शन कंपनी से लौज पर ली गई जमीन के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। इस संबंध में किरौट सोमैया ने कहा है कि उन्होंने मुंबई पुलिस, आयकर विभाग, ईडी कार्यालय में शिकायत दी है। सोमैया का आरोप है कि 15 कोविड सेंटर की तरह मुंबई के 15 कोविड सेंटरों के लिए 700 करोड़ रुपये का किराया घोटाला किया गया है।

सदन में वोट के लिए बीमार मनमोहन को लाने पर भाजपा भड़की -अमानवीय परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस-आप ने दी संविधान की दुहाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस व आप ने अमानवीय परिस्थितियों के बावजूद मनमोहन सिंह को वोट डालने के लिए राजसभा में बुलाया। इस पर भाजपा बुरी तरह से भड़क गई। बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर राजसभा में सोमवार को वोटिंग हुई, जिसमें बाजी एनडीए गठबंधन के हाथ लगी। फिर भी इंडिया के नाम से एकजुट हुए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत शोक दी। उसे एनडीए के 131 वोटों के मुकाबले 102 ही मिले हैं, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग में एक-एक वोट के लिए कड़ी मशकत की। यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे 90 वर्षीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी उसने सदन में वोट के लिए बुलाया था। पूरी बहस और वोटिंग के दौरान मनमोहन सिंह वॉलचेयर पर बैठे नजर आए। इस बीच इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने मनमोहन सिंह को उभर और खराब तबीयत के बाद भी सदन बुलाने को अमानवीय बताया है। इस पर भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि देश कांग्रेस के इस पागलपन को याद रखेगा। भाजपा ने ट्वीट किया, याद रखें देश, कांग्रेस की ये सनक! कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को बैर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी वॉलचेयर पर बैठाए रखा जो भी अपना बेईमान गठबंधन जादि रखने के लिए! बेहद शर्मनाक! वहाँ इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के पहुंचने को

अगर देश की 82 फीसदी आबादी...हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ का बड़ा बयान

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि वृद्धि देश में 82/लोग हिंदू हैं, इसलिए भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने स्वयंभू धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग का जिक्र करते हुए यह बात कही और कहा कि इस मामले पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह डेटा द्वारा समर्थित एक स्थापित तथ्य है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 82 प्रतिशत हिंदू हैं। यहां कोई बहस नहीं है कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक नेता द्वारा हिंदवाड़ा में बागधर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री



का स्वागत करने के बाद कमलनाथ के बड़े सांसद नकुल कमलनाथ पर निशाना साधने के एक दिन बाद आया है। राजद और कांग्रेस दोनों विपक्षी गुट इंडिया का हिस्सा हैं। आलोचना ने नवगठित विपक्षी गठबंधन के भीतर आंतरिक संघर्ष की अटकलें बढ़ा दीं। राजद के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की भेजबानी के लिए कांग्रेस सांसद नकुल कमलनाथ की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बागधर धाम प्रमुख ने खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। तिवारी ने कहा कि हम शास्त्री का उनके हिंदुत्व एजेंडे के लिए विरोध करते रहे हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, किसी अन्य विचारधारा से नहीं। वया हम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इतनी नीचे गिर जाएंगे? नकुल कमलनाथ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए स्वयंभू बाबा का स्वागत किया था।

भाजपा सांसद का राहुल गांधी पर तंज...आप सावरकर कभी नहीं हो सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मंगलवार को जोरदार बहस हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई के बहस की शुरुआत करने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए। उनके बोलने पर बार-बार हंगामा होता रहा। इस बीच सांसद दुबे ने राहुल पर तंज कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दिया है, जजमेंट नहीं दिया है। कह रहे हैं कि मामी नहीं मांगूंगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ। निशिकांत ने ललकारते हुए कहा, आप कभी सावरकर हो भी नहीं सकते जिनगी में... 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारे हैं। कभी सावरकर नहीं हो सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया बना है न, यहाँ कुछ सांसद ही फुल फॉर्म बत पाएंगे। लेकिन ये इंडिया-इंडिया बत कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा सांसद ने सोनिया गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के पास बस दो काम हैं। भाजपा सांसद की बात सुनकर कांग्रेस के सदस्य शोर मचाने लगे, हालांकि सोनिया गांधी मुस्कुराने लगीं। निशिकांत ने कहा कि मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोले

एससी/एसटी कानून, आईपीसी का दुरुपयोग न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है: कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों के खिलाफ दायर एक मुकदमे को रद्द करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के दुरुपयोग का इससे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि एससी/एसटी कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत झूठे मामले आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं। अदालत ने कहा, "यह मामला इस कानून के प्रावधानों तथा आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों के दुरुपयोग का 'अनोखा' उदाहरण बन गया। यह उन मामलों में से है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं और अदालतों का अच्छा-खासा समय बर्बाद करते हैं, चाहे वह मजिस्ट्रेट अदालत हो, सत्र अदालत या यह



अदालत (उच्च न्यायालय), जबकि वे मुकदमे अटक रहे जताते हैं जिनमें वादी वाकई पीड़ित होते हैं।" न्यायमूर्ति एम. नागप्रसाद ने रसिक लाल

पटेल और पुरुषोत्तम पटेल की याचिका पर हाल में दिये फैसले में कहा, "मामले के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद यह सामने आया कि इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया

गया है। यह मामला उन सैकड़ों मामलों का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिनमें गलत उद्देश्यों या समानांतर चलने वाले मुकदमों में आरोपियों पर दबाव बनाने के लिए इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया।" याचिकाकर्ताओं के पिता के. जे. पटेल ने 50 साल पहले कृष्णमूर्ति नामक एक व्यक्ति से संपत्ति खरीदी थी। कृष्णमूर्ति का बेटा पुरुषोत्तम दोनो भाइयों (याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ संपत्ति को लेकर एक दीवानी मुकदमा लड़ रहा है। उसने 2018 में पटेल बंधुओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करायी और उन पर एससी/एसटी अत्याचार कानून तथा आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनो भाइयों ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। दोनो भाइयों के वकील ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के पास पिछले 50 साल से इस संपत्ति का मालिकाना हक है तथा शिकायतकर्ता का परिवार इन सभी बातों को अच्छी तरह जानता है। न्यायमूर्ति नागप्रसाद ने कहा कि दीवानी मुकदमे को आपराधिक रखा गया। अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमे को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुरुषोत्तम ने दावा किया था कि संपत्ति के 50 साल पहले हुए लेनदेन में फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ये दस्तावेज 50 वर्ष से सार्वजनिक हैं तथा इन्हें कभी चुनौती नहीं दी गयी। उच्च न्यायालय ने पटेल बंधुओं की याचिका मंजूर कर ली तथा उनके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया।

विश्व आदिवासी दिवस : एक अवलोकन

डॉ. (प्रो.) तपनकुमार शांडिल्य

आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव माना रहा है; आजादी के नायकों को याद कर रहा है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि आदिवासियों के राष्ट्र प्रेम और इस प्रेम में दिए उनके अनेक बलिदान को भी याद किया जाए। 1790 का 'दामिन विद्रोह', 1828 का 'लरका आन्दोलन', 1855 का संथाल का विद्रोह, यह सभी ऐसे आंदोलन रहे जिसमें मरी संख्या में आदिवासी ने अपना बलिदान दिया। आदिवासियों या वनवासियों की अपनी मिट्टी के प्रति प्रतिबद्धता ही राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और सम्मान है। आदिवासी राष्ट्र को सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जागृत करने का काम भी अपने लोक संचार माध्यम के जरिये करते रहे हैं। बंगला लोक नाट्य 'जात्रा' का उपयोग स्वतंत्रता संघर्ष में खूब किया गया।

विश्व आदिवासी दिवस पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न आदिवासी समुदायों के सम्मान और उनके सांस्कृतिक धरोहर को याद करने का एक विशेष अवसर है। हर साल 9 अगस्त को मनाया जाने वाला यह पर्व एकता और समरसता का प्रतीक है जिसमें विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोग सम्मिलित होते हैं और अपने भाषाएँ संस्कृतिएँ और परंपराओं के माध्यम से एक-दूसरे को समझते हैं। यह दिन आदिवासी समुदायों के अधिकारों और समस्याओं को भी उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें सम्मान दिलाना है। इस दिन को समर्पित करने का मकसद सामाजिक न्याय, समरसता, और समानता को प्रोत्साहित करना है। यह अवसर विश्व भर के लोगों को एक साथ मिलकर आदिवासी समुदायों के संघर्षों और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान दिखाने का अवसर है। विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनजीए) के द्वारा ऐलान किया गया था।

पुरातन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को 'अल्किवा' नाम से संबोधित किया गया एवं महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन (पहाड़ पर रहने वाले लोग) से संबोधित किया। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' पद का उपयोग किया गया है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के निम्न आधार हैं- आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच या पिछड़ापन। आदिवासियों को देशज ज्ञान परंपरा काफी समृद्ध है। इसकी समृद्धि ही इसके शोषण का कई बार कारण भी बनती है। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े औद्योगिक घराने के लोग आदिवासियों के देशज ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके साथ छल करते हैं। इसके ढेर सारे उदाहरण संबंधित क्षेत्रों में मिल जाते हैं। वर्जिनियस झाड़ा की अथक्षता में एक उच्च स्तरीय कर्मिटा का गठन 2013 में किया गया था। इस कर्मिटा के द्वारा जनजाति में मूल शब्द 'जाति' को परिभाषित किया गया। इस शोध-पत्र में यह बताया गया है कि कैसे विस्थापन के बाद आदिवासी जातियाँ अपने मूल व्यवसाय को छोड़ अन्य कार्यों में लग जाती हैं, जिस कारण से एक समय के पश्चात ये आदिवासियाँ धीरे-धीरे अपने वास्तविक एक आधिकारिक ज्ञान को भूलने लगती हैं।

आदिवासियों के पास डिजास्टर, डिफेंस और डेवलपमेंट का अद्भुत ज्ञान है। ऐतिहासिक पुस्तकों एवं ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कैसे मुगल या अंग्रेज जब भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं लेकिन जब वे आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने की सोचते हैं तो उन्हें मुह



की खानी पड़ती है। इसी प्रकार अंडमान के जरावा आदिवासी के द्वारा सुनामी जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा में भी खुद को बचा लेने एवं इसका अंशला लगा लेने कि कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आने वाली है ने इस विषय क्षेत्र के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आदिवासियों के पास डिजास्टर की अद्भुत समझ है। इसी प्रकार आदिवासी समाज में एक मदद की परंपरा है जिसे 'हलमा' कहते हैं। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने संपूर्ण प्रयासों के बाद भी खुद पर आए संकट से उबरने में असमर्थ होता है तब उसकी मदद के लिए सभी ग्रामीण जुटते हैं और अपने निःस्वार्थ प्रयत्नों से उसे उस मुश्किल से बाहर निकालते हैं। यह एक ऐसी गहरी और उदार परंपरा है जिसमें संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता की जाती है। यह परंपरा या ज्ञान चर्चा में तब आई जब 2018 में देश में भयानक जल संकट को देखते हुए आदिवासियों ने इस बार हलमा का आह्वान धरती मां के लिए किया। इसका परिणाम यह रहा कि मात्र कुछ दिनों में देश के अन्य-अन्य स्थानों पर निशुल्क हजारों जल संरक्षण केंद्र तैयार कर दिए गए। इस देशज ज्ञान की खास बात यह भी रही कि बड़े महानगरों से आईआईटी कर चुके इंजीनियर और कुशल तकनीशियन भी इसमें अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ शामिल हो रहे हैं। निमित्त धाकड़ पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन जब 2015 में वे इस परंपरा से जुड़े तो इस परंपरा से बहुत प्रभावित हुए, इसका परिणाम यह रहा कि 2017 से वे अपनी नौकरी छोड़ कर इसी परंपरा के तहत लोगों को जागरूक एवं कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रो. विकास कुमार (समाजशास्त्री) इलाहाबाद ने भी अपने हाल के शोध में गुमला जिला के

आदिवासियों का अध्ययन किया है। इन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आदिवासियों ने अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए किया। आजादी के आंदोलन में उनके योगदान को याद करना 'आजादी के अमृत महोत्सव' को पूर्ण करेगा। आदिवासियों का राष्ट्र के प्रति वह अमृत भाव ही था जिसने सिद्ध और कानू, तिलका और मांडी, बिरसा मुंडा इत्यादि वीर बौद्धों को जन्म दिया। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव माना रहा है; आजादी के नायकों को याद कर रहा है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि आदिवासियों के राष्ट्र प्रेम और इस प्रेम में दिए उनके अनेक बलिदान को भी याद किया जाए। 1790 का 'दामिन विद्रोह', 1828 का 'लरका आन्दोलन', 1855 का संथाल का विद्रोह, यह सभी ऐसे आंदोलन रहे जिसमें भरी संख्या में आदिवासी ने अपना बलिदान दिया। आदिवासियों या वनवासियों की अपनी मिट्टी के प्रति प्रतिबद्धता ही राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और सम्मान है। आदिवासी राष्ट्र को सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जागृत करने का काम भी अपने लोक संचार माध्यम के जरिये करते रहे हैं। बंगला लोक नाट्य 'जात्रा' का उपयोग स्वतंत्रता संघर्ष में खूब किया गया।

लोकमान के परंपरागत रूप 'पाला' का उपयोग भी जनजागरूकता एवं स्वतंत्रता आंदोलन में किया गया। इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जहां लोक संचार माध्यम के जरिये आदिवासियों ने आजादी की

अलख जगाए रखी। इस प्रकार आदिवासियों की यह देशज ज्ञान परंपरा देश-दुनिया के लिए सशक्त समाधान का माध्यम बन सकती है, जरूरत है इस देशज ज्ञान को चिह्नित कर इसे वैज्ञानिक मान्यता देने की। देश के भूपूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने कहा था कि यदि वाकई हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो देश में वैज्ञानिक शोध के अवसरों को न केवल आसान करने की जरूरत है, बल्कि भारत के अशिक्षित ग्रामवासी या सामान्य जन जो आविष्कार कर रहे हैं, उन्हें भी वैज्ञानिक मान्यता देकर उपयोग करने की जरूरत है।

आदिवासी लोगों को अपने अस्तित्व, संस्कृति, और सम्मान को बचाने के लिए कठिन से कठिन संघर्ष करने पड़े रहे हैं और इतना ही नहीं पूरे विश्व में नक्सलवाद, रांभेद, उदारीकरण तथा अन्य कई समस्याओं से अपने अस्तित्व और सम्मान को बचाने के लिए कठिन से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक आंकड़ों के अनुसार अभी झारखंड क्षेत्र की कुल आबादी में 28% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं तथा इन समुदाय में कई जातियाँ आती हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं जैसे संथाल, बजरा, बिहोर, चरो, गोंड, हो, खोंड, लोहरा, माई पहाड़िया, मुंडा, ओरांव आदि 32 से अधिक आदिवासी समूह के लोग इसमें सम्मिलित हैं और इसी कारण से हर साल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसमें आदिवासी संस्कृति और उनके सम्मान को बचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है इसे संयुक्त राष्ट्र पर कई देशों की सरकारी संस्थाओं के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोग, वे आदिवासी संगठन के साथ मिलकर दुनिया भर में सामूहिक उत्सव का आयोजन करते हैं, जैसे नृत्य, आदिवासी दिवस पर भाषण, आदिवासी दिवस पर शायरी, आदिवासी दिवस की शुभकामनाएँ, रूढ़ियों के विपरीत, स्वदेशी लोग संगठित समाजों में रहते हैं और उन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था, अपनी भाषा और परंपराओं को परिभाषित किया है। स्वदेशी लोगों द्वारा निर्भाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं:

-उनकी कृषि तकनीकों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला होने के लिए विकसित किया गया है।

-वे जंगलों, नदियों, मिट्टी आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए काम करते हैं।

-वे जिन क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं उनमें दुनिया की 80% जैव विविधता शामिल है।

-उनकी जीवन शैली और प्रथाएँ अत्यधिक टिकाऊ हैं।

-वे दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं अगर उनके लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाया जाए।

संपादकीय

चिन्तन - मनन (जीवन)

जीवन में कोई भी कार्य हम करे तो चिन्तन - मनन उसके लिये आवश्यक है। कहते हैं कि सही चिन्तन से किया हुआ कार्य सफलता को प्राप्त होता है। किसी भी रचनात्मक काम की जन्मस्थली कल्पना है। पहले मन में एक योजना की कल्पना उठती है। फिर उसे लिपिबद्ध करने के लिए कलम चलती है। फिर उस पर अच्छी तरह सही से चिन्तन मनन होता है। तब हमारी मानसिकता क्रियान्वित के लिए आगे बढ़ती है। इस पृष्ठभूमि कोतकनीकी भाषा में हम सजातमक कल्पनाशीलता कहते हैं। इसी के सहारे बड़े से बड़े छोटे से छोटे सारे काम क्रियान्वित होते हैं। कठिन परिस्थिति और हताशा का चोली-दामन कासाथ है। ऐसे में आदमी निराशा की ही बात पहली मानसिक प्रतिक्रिया से करता है। विरले ही होते हैं जो इस घड़ी में भी नहीं डगमगाते और संयत रह पाते हैं। एक छोटा सा प्रयत्न हमारी सोच की दिशा को बदल सकता है। एक सही से सकारात्मक विचार काचिन्तन-मनन। करते-करते मनन में हृदयंगम हो जाती है सकारात्मकता। सकारात्मकता का अभ्यस्त और कठिनतम परिस्थिति में वहकभी भी नहीं होगा मानसिक रूप से त्रस्त। मनन करें वह मंथन करें की हम क्या कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं? लोभ और अनावश्यक चीजोंके मायाजाल में फँस रहे हैं। हम इस संसार की मृगतृष्णा से अपनी बाजी स्वयं हार रहे हैं हलकदम हलम विवेकशील प्राणी होकर भीविवेकशून्य हो रहे हैं। क्योंकि हमें जिन्हें छोड़ना है उन्हें ही हम जोड़ रहे हैं। जदिगी तो हमारी हल्की-फुल्की है हम हमारी ख्वाहिशों केबोझ तले दब रहे हैं। अपनी इच्छाओं से जो बेजोड़ नाला हमने बना रखा है उस गठबंधन को हमें तृप्ति की मजबूत डोर से तुलत बाँधनाहोगा। अल्प समय का सुख और दीर्घकालीन खुशी का फर्क शान्ति से समझना होगा। उसको हृदयंगम करना होगा की अंत में खालीहाथ ही है जाना। ये जगत का सुख तो है सपना, बड़े जितना, घटे उतना। बस पुण्य की कमाई पर हक अपना है। और-और की व्यर्थसुधा हमें संसार से बाँधने वाली- क्षणिक आनन्द देकर, दीर्घ खुशियों को छीनने वाली है। मन से मनन करते हुए मनन। मन- मनन - मनन। इस तरह हर अक्षर का अपना - अपना महत्व होता है। मन शब्द के पीछे जब जुड़ जाये न अक्षर तो मन का उच्चारण बन जाता हैमनन। एक बिन्दु पर रहता है हमारा केन्द्रित क्रियाशील मन। भीतर ही भीतर चलता है उसका चिन्तन। जिससे निर्णय शक्ति का संवर्धनहोता है। वह सही से सफलता का वरण होता है। यदि मन का मनन रूप में हो अगर अवतरण तो मन का होगा सदा सकारात्मकअवलोकन हर अक्षर का अपना महत्व होता है। मन शब्द के आगे जुड़ जाये न अक्षर। तब मनन शब्द का जन्म होता है। तब मन कापूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाता है। नमस्कार या झुकना है- मन का मनन मनन बन मन का अहंकार रहित हमें होना है। क्रतुता व मुदुताका विकास करता है। चंचल मन को शान्त व निर्विकार बनाता है।

नमन कर आत्मगुणों के विस्तार को पाना है। गतिशील मन पर यदि रोक लगाना चाहते हो तो न अक्षर का मन से सदा जुड़े रहना जरूरी है। चाहे आगे या पीछे पर सदा साथ निभाना जरूरी है। जिससे मनन और मनन बन मन द्वारा सदा अशुभ कर्मों का शमन हमारे द्वारा होगा। मन- मनन-मनन को इस तरह हम सही से समझे। अपनी शक्ति को पहचान कर, ज्ञान की अनन्तता को पाकर आदि हम जीवन के वास्तविक सुख से मुखातिब होने के चिन्तन के साथपीपूष प्रवाह में जीवन को झोके।



प्रदीप छाजेड़ (बोरावड़)



सनत जैन

केन्द्र सरकार कई दशकों बाद बिना सेटलाइट, केबिल और इंटरनेट के बिना स्मार्टफोन पर टीवी चैनल लोग देख पाएँ, इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की पहल पर आईआईटी कानपुर ने कार्य शुरू कर दिया है। यह माना जा रहा है, कि जल्द ही ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण स्मार्ट फोन और स्मार्ट टीवी पर संभव होगा। 2005 से यह तकनीकी दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। स्मार्टफोन और घरों में लगी हुई स्मार्ट टीवी, एंड्रॉइड के माध्यम से संचालित हो रही हैं। पहले दूरदर्शन की टीवी देखने के लिए एंटीना लगाना पड़ता था। जिसमें टीवी के चैनल जो दूरदर्शन से सेटलाइट के माध्यम से प्रसारित होते थे। वह छतरी में लगे एंटीना के द्वारा सिग्नल रिसीव कर टीवी के माध्यम



जयसिंह रावत

अना हजारों के आंदोलन के फलस्वरूप 1 जनवरी 2014 को अस्तित्व में आए भारत के लोकपाल एवं लोकयुक्त अधिनियम की धारा 63 में कहा गया था कि संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के अंदर सभी राज्यों की विधानसभाएँ इस एक्ट के अनुरूप लोकयुक्त कानून बनाएँगी और उस कानून के आधार पर राज्यों में लोकयुक्त का गठन होगा, लेकिन 9 साल गुजर गए और देश के 28 राज्यों में से उत्तराखंड सहित 8 राज्यों ने लोकयुक्त का गठन नहीं किया। कुछ राज्यों में लोकयुक्त संगठन में न्यायिक सदस्यों के पद खाली हैं। कुछ राज्यों ने अब तक कानून तक नहीं बनाएँ, जबकि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए राज्यों को फटकार लगा चुका है। भ्रष्टाचार देश के सामने एक गंभीर चुनौती बन कर खड़ा है। नागरिक अदालत की कह चुका है कि भ्रष्टाचार नागरिकों के सम्मानता और जीवन के अधिकार संबंधी सिवाधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। वास्तव में भ्रष्टाचार निष्पक्षता, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जो नागरिकों के अधिकारों की

बिना इंटरनेट के भी स्मार्टफोन में दिखेंगे टीवी चैनल

से दिखते थे। हर घर में सिग्नल रिसीव करने के लिए छतरी लगी हुई दिखती थी। सरकार ने एक बार फिर पुरानी तकनीकी का सम्मिश्रण करने की पहल की है। इसमें टेलीविजन चैनल, जो सेटलाइट नेटवर्क पर आधारित हैं। उनके सिग्नल अब एंड्रॉइड टीवी और एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर रिसीव करके चैनल दिखाने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। डायरेक्ट टू मोबाइल यानी डी 2 एम तकनीकी से स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी में चैनल देखा संभव होगा। आईआईटी कानपुर ने देश में इस सेवा को शुरू करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है, कि प्रसारणकर्ता डी 2 एम नेटवर्क के ऐप से क्षेत्रीय टेलीविजन, रेडियो, क्षेत्रीय कंटेंट, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, आपदा से जुड़ी सूचनाएँ, रेडियो सिग्नल ऐप की सुविधा उपलब्ध होगी। बिना इंटरनेट की सहायता से डी 2एम ऐप के माध्यम से कम दाम पर यह सुविधाएँ आम आदमी को उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है।

केन्द्र सरकार जो नवीन तकनीकी लाने का निर्णय लिया है। वह ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण होगा। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी में लगे रिसीवर, रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ेगा। इसके लिए सरकार 526-582 मेगा हर्ट्ज बैंड पर सेवाएँ शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसमें रेडियो के सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। इस बैंडविथ का उपयोग अभी रेडियो

ट्रांसमिशन के लिए होता है। भारत में इस समय 22 करोड़ परिवारों के पास स्मार्ट टीवी है। इसी तरह लगभग 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। टेलीविजन चैनल प्रसारण के अभी कई माध्यम हैं। टीवी चैनल को सेटलाइट नेटवर्क, अलग-अलग कंपनियों की ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सेवा और केबल का सहारा लेना पड़ता है। केबिल ऑपरेटर इसका विरोध कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटर देश में लाखों की संख्या में हैं। इनमें करोड़ों लोग काम करते हैं। उनका धंधा बंद हो जाएगा। वहीं टेलीविजन चैनलों को उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए अभी कई माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दक्षिण कोरिया और हांगकांग में यह तकनीकी 2005 से काम कर रही है। वहां पर इसे मोबाइल टेलीविजन भी कहा जाता है। सरकार का मानना है, कि 100 करोड़ स्मार्ट टीवी और स्मार्ट मोबाइल फोन तक ऐप के माध्यम से भारत में डी 2एम तकनीकी का उपयोग कर शैक्षणिक कंटेंट, अति आवश्यक सूचनाएँ, आपदा से जुड़ी हुई जानकारी, वीडियो, रेडियो के अलावा डाटा से चलने वाले ऐप की सुविधा लोगों को सस्ते दाम पर बिना इंटरनेट के मिलना शुरू हो जाएगी। दूरदर्शन के क्षेत्र में भी जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। वहां के उपभोक्ताओं को भी समान अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए मेगाहर्ट्ज बैंड पर संचालित होने वाली, यह तकनीकी काफी कारगर साबित होगी। सरकार जो भी

काम करती है। उसमें अधिकार कायम करने की कोशिश होती है। जिस एप के माध्यम से यह सेवाएं चलाई जाएंगी। उनकी दरें तय करना और उनकी सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार को कठोर नियम बनाने की जरूरत होगी। सभी जगह सिग्नल प्राप्त हों, इसके लिए उपकरण लगाने होंगे। अभी जो भी स्मार्टफोन हैं, उनमें सिग्नल नहीं मिलते हैं। कंपनियाँ दावा करती हैं, कि उनका नेटवर्क सारे देश में है। हर राज्य में है। लेकिन सिग्नल की समस्या हमेशा बनी रहती है। दक्षिण कोरिया, हांगकांग और जर्मनी में यह सेवाएँ निर्बाध रूप से सफल हैं। सरकार मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर जो सेवाएँ शुरू करती है। टीवी की जाती है। इसमें कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय करने की जरूरत है। विशेष रूप से सिग्नल हर जगह पर और एक निश्चित बैंडविथ पर सतत सेवाएँ उपलब्ध हों। तभी यह प्रयास सार्थक माना जाएगा। सरकार को उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियों से अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाना आम उपभोक्ता के लिए भारत में आसान नहीं है। उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और ठगी की जाती है। उसकी शिकायत करने में उपभोक्ताओं को वर्षों तक न्याय नहीं मिलता है। उल्टे मुकदमे बाजी में लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उपभोक्ता को बेहतर सेवाएँ मिलें। सरकार को इस दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए।

लोकायुक्त : आखिर डरते क्यों हैं राज्य



सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भ्रष्टाचार अक्सर सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग, रिक्खोरी, गबन और सत्ता के दुरुपयोग के साथ-साथ अन्य प्रकार के कदाचार को जन्म देता है। अभी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करना या न करना शासन-प्रशासन के हाथ में है, लेकिन लोकायुक्त व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सीधे लोकायुक्त से किसी के भी खिलाफ जांच की मांग कर सकता है। लोकपाल का डर ही था कि 1968 से लेकर 2013 तक संसद लोकपाल का कानून पास नहीं कर सकी। लोकपाल कानून बनने के 5 साल बाद केन्द्र में पिनार्की चंद्र घोष को लोकपाल के तौर पर नियुक्ति हो सकी मगर उनका कार्यकाल 27 मई 2022 को पूर्ण होने के बाद भी नए लोकपाल की नियुक्ति के बिना केन्द्र में प्रभारी लोकपाल से काम चलाया जा रहा है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल-लोकायुक्त कानून के अस्तित्व में आने के बाद भी 28 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 9 ने अभी तक केन्द्रीय कानून के अनुरूप या समरूप अपने

लोकायुक्त कानून में संशोधन नहीं किया। देश के 28 राज्यों के साथ ही 3 केन्द्र शासित प्रदेशों से जुटते ये इन आंकड़ों के अनुसार 8 ने लोकायुक्त का गठन नहीं किया। इन राज्यों में उत्तराखण्ड, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पुदुचेरी हैं। जम्मू-कश्मीर में जो संस्था थी वह भंग है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद भी उत्तराखण्ड जैसे कुछ राज्यों ने लोकायुक्त के गठन की पहल नहीं की। सन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 राज्यों के मुख्य सचिवों को अपने यहां यथाशीघ्र लोकायुक्तों के गठन के निर्देश दिये थे। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी आवश्यक उपलोकायुक्तों (सदस्य) की नियुक्ति नहीं हुई। आज एक देश एक कानून की बात तो होती है मगर लोकायुक्त कानूनों में एकरूपता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां शिकायत दर्ज करने का शुल्क मात्र 3 रुपये है, वहीं गुजरात और उत्तर प्रदेश में यह शुल्क 2000 रुपये रखा गया है। कुछ राज्यों ने संसद द्वारा

पारित लोकायुक्त कानून के मजमून को अपनाने की बजाय अपनी सुविधानुसार कानून बना दिए। उत्तराखण्ड अपना अलग कानून बनाने का तर्क देकर मौजूदा कानून के अनुसार लोकायुक्त का गठन नहीं कर रहा है। न्यायालयों के निर्देश के बावजूद लोकायुक्त का गठन करने की बजाय राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जबकि केन्द्र सरकार स्वयं समान नागरिक संहिता बनाने जा रही है। अगर केन्द्र का कानून बनता है तो अनुच्छेद 254-क के अनुसार उत्तराखण्ड के कानून का अस्तित्व नहीं रह जाता है। शासन प्रशासन में शुचिता और सुशासन के लिए एक सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की कवालत सन-1960 के दशक से शुरू हो गयी थी। इस तरह की एक संस्था की परिकल्पना सबसे पहले 1963 में विख्यात न्यायविद डा एल.एम.सिंघवी ने की थी। कई चरणों के बाद 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। केन्द्र में लोकपाल-लोकायुक्त कानून आने के बाद ओडिशा पहला राज्य था जहां 14 फरवरी 2014 को संसद द्वारा पारित कानून के मुताबिक लोकायुक्त कानून बना था और उसके बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य था, जिसका लोकायुक्त कानून 26 फरवरी 2014 को अस्तित्व में आया था। लेकिन इतने साल बाद भी उस कानून के अनुसार उत्तराखण्ड को एक अदद लोकायुक्त नहीं मिल सका। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा कानून को नकार कर 100 दिनों के अंदर एक नया मजबूत लोकायुक्त कानून लाने के साथ ही लोकायुक्त के गठन का वायदा किया गया था लेकिन न तो नया कानून आया और न ही सौ दिन की बजाय 6 साल गुजरे पर भी नया लोकायुक्त अस्तित्व में आया। ऐसी ही मिलती जुलती कथा अन्य उन राज्यों की भी है जो लोकायुक्त से वंचित हैं।



बीबीए के बाद क्या है करियर ऑप्शन

बीबीए करने के बाद आपको एमबीए में एडमिशन लेने के अतिरिक्त मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, ड्रॉट मैनेजमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि में अपने पैशन और इंटररेस्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म कोर्स भी करते रहना चाहिए। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाल के दिनों में बेहद तेजी से यह कोर्स लोकप्रिय हुआ है। दुनिया में छोटे से लेकर बड़े व्यापार लोग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग-बाग बिजनेस करें, ताकि देश की इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ती रहे।

इन तमाम चीजों में अगर एक कॉमन फेक्टर खोजा जाए तो वह यह है कि नए-पुराने सभी व्यापारों में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की अहमियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चूंकि ह्यूमन रिसोर्स से लेकर सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तकनीकी डिपार्टमेंट, नेटवर्किंग और दूसरे विभाग बगैर मैनेजमेंट के चल ही नहीं सकते हैं। चाहे आप आईटी की बात कर लें, चाहे आप सर्विस की बात कर लें, या फिर किसी और डिपार्टमेंट की, जाहिर है कि मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में बीबीए को एक स्टूडेंट करियर के रूप में बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर चुन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कारपोरेट लौडर बनने का मौका मिल जाता है। अगर साधारण तौर पर भी बात की जाए, तो करियर ग्रोथ के लिए बीबीए के बाद कैडिडेट्स को एमआईएस अर्थात् मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम का सर्टिफिकेशन कोर्स करने की सलाह भी एक्सपर्ट देते हैं। सॉफ्टवेयर की जानकारी से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही कारपोरेट वर्ल्ड में इन चीजों का बेहतर से बेहतर प्रयोग होता है, जिससे आपको काफी आसानी होगी। इसी प्रकार कम्युनिकेशन पर भी आपको खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन वही कर सकता है।

जो तमाम पक्षों से बेहतरीन कम्युनिकेशन करने की दक्षता रखता हो।

मार्केट के कई पक्ष होते हैं, और उनके साथ आप तभी ठीक तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जब आप बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल अपने भीतर रखते हैं। इसके लिए आपको अपने कलीग्स के साथ इंटरैक्शन करते रहना चाहिए, तो भिन्न-न्यूज पेपर्स भी पढ़ते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मार्केट ट्रेंड को आप अपने ध्यान में हमेशा बनाए रखें, जिससे चीजों को समझने की आपकी दक्षता काफी बढ़ेगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीबीए करने के बाद आपको एमबीए में एडमिशन लेने के अतिरिक्त मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, ड्रॉट मैनेजमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि में अपने पैशन और इंटररेस्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म कोर्स भी करते रहना चाहिए। इससे आपकी



एमबीए स्टूडेंट की डिमांड आज भी काफी ज्यादा है, और तमाम कंपनियां प्रबंधन में अलग-अलग बैकग्राउंड के एमबीए लड़कों को लेना प्रीफर करती हैं, क्योंकि कार्य करने वाले तमाम लोग तो किसी भी जगह पर उपस्थित होते हैं, पर बेहतरीन ढंग से प्रबंधन करना और कार्य कराना हर कंपनी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है।

एमबीए का मतलब प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, तो प्रबंधन आप तभी करेंगे जब लोगों के बीच में रहेंगे। लोगों के बीच में रहने का मतलब नेटवर्किंग से भी जुड़ा होता है और ऐसी स्थिति में पार्टी- गैदरिंग इत्यादि में आपकी मौजूदगी जरूरी है। करियर की चाहे जितनी भी संभावनाएं सामने आ जाएं, ट्रेडिशनल कोर्सज का अपना स्टाइल है। आप इतना जान लीजिए कि एमबीए स्टूडेंट की डिमांड आज भी काफी ज्यादा है, और तमाम कंपनियां प्रबंधन में अलग-अलग बैकग्राउंड के एमबीए लड़कों को लेना प्रीफर करती हैं, क्योंकि कार्य करने वाले तमाम लोग तो किसी भी जगह पर उपस्थित होते हैं, पर बेहतरीन ढंग से प्रबंधन करना और कार्य कराना हर कंपनी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है। इसीलिए एमबीए करने वाले लड़कों को अच्छी खासी सैलरी भी

एमबीए की पढ़ाई की है तो ऐसे मिल सकता है मोटा वेतन

मिलती है। हालांकि अगर आप अपने करियर से लापरवाही बरतते हैं, इंटरव्यू को लेकर लापरवाही बरतते हैं, तो आप सैलरी के मामले में पिछड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि एमबीए करते समय और उसके पहले क्या सावधानियां आपको अच्छा खासा वेतन दिला सकती हैं।

विषय का रखें ध्यान

जी हौं! 12वीं के तत्काल बाद आपको विषयों के चुनाव में सावधानी बरतना चाहिए। अगर आप बाद में एमबीए करना चाहते हैं,

तो ग्रेजुएशन में ही उन विषयों को चुनकर रखना चाहिए, जो बाद में एमबीए करने में आपकी मदद करें। साथ ही इंग्लिश पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इंग्लिश को अच्छा खासा प्रेफरेंस देती हैं, तो शुरू से ही अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, तो बाद के दिनों में आप इन्हें महारत हासिल कर सकते हैं।

बिजनेस वर्ल्ड पर नजर रखें

शेयर मार्केट की उठापटक, मार्केट ट्रेस करना, कंपनी को रिस्ट्रक्चर किस तरह से

दुनिया की कोई ताकत आपको मोटा वेतन से और एक सफल करियर बनाने से नहीं रोक सकती। जहाँ तक एमबीए में प्रवेश के लिए योग्यता की बात है तो आपको ग्रेजुएशन में डिग्री के साथ-साथ कम से कम 50% मार्क्स होने आवश्यक हैं और अलग-अलग पेटर्न के एग्जाम देकर आप इस में प्रवेश ले सकते हैं। मुख्य रूप से एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एमबीए इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स मौजूद हैं। इसके लिए ऊपर बताये गए पॉइंट्स को अवश्य ही ध्यान में रखें और तभी आपका कांसेप्ट क्लियर रहेगा और आप एक सफल करियर और मोटी तनखाह की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।

लक्ष्य विलयन रखें

ध्यान रखिए! प्रबंधन के विषयों में उद्देश्य समझना जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप खुद से क्या चाहते हैं? अगर यह सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से क्लियर हैं, तो उन उद्देश्यों को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, किंतु अगर आप खुद ही विलयन नहीं हैं, तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं, और आप को नहीं समझ में आएगा कि आप जिदगी से वास्तव में चाहते क्या हैं? सोचिये-समझिये कि आप अपने करियर से चाहते क्या हैं और अपना लक्ष्य विलयन रखें, और उसी के अनुरूप तैयारी करें। इसी के माध्यम से अगर आप इन विषयों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो

मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की अहमियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ह्यूमन रिसोर्स से लेकर सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तकनीकी डिपार्टमेंट, नेटवर्किंग और दूसरे विभाग बगैर मैनेजमेंट के चल ही नहीं सकते हैं। चाहे आप आईटी की बात कर लें, चाहे आप सर्विस की बात कर लें, या फिर किसी और डिपार्टमेंट की, जाहिर है कि मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाता है।

दक्षता तो बढ़ती ही है, आपका फोकस विलयन होने से आप सफलता की राह पर इतनी ही तीव्रता से आगे की ओर बढ़ सकते हैं।

ध्यान दीजिये कि अगर आप साधारण कॉलेज से बीबीए करते हैं, और मार्केट ट्रेस पर नजर बनाए रखते हैं, तो शुरुआत में 12000 से 18000 तक की मासिक वेतन पर आपको शुरुआत मिल सकती है, और जैसे-जैसे आप अनुभव में दक्ष होते जाएंगे, वे-वे लीडर्स की पोजीशन आपको अपनाती चली जाएगी। हालांकि बीबीए के बाद आपको एमबीए करने की सलाह भी कई एक्सपर्ट आपको देंगे और यह बेहद नॉर्मल है। बीबीए के बाद एमबीए तकरीबन 2 वर्ष का है और तमाम टॉप कॉलेज आपको आसानी से एक से बढ़कर एक आषान देते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कैट और मेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास करने पड़ते हैं, और फिर एमबीए में आप मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड इत्यादि दूसरे स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, और अपने करियर को चुन सकते हैं। अगर आप के पास समय कम है और आप जॉब कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव एमबीए में भी आपको बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं, और फिर बाद में आप हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट एजेंसी, मैनुफैक्चरिंग एजेंसी और एफएमसीजी

ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपने करियर को सोंप दे सकते हैं, तो बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एमबीए नहीं कर पाते हैं, तो मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। हालांकि कई जगह पर इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एमबीए जहाँ डिग्री कोर्स है, जबकि पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स माना जाता है। परंतु अगर आपने किसी बेहतरीन कॉलेज से डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो बीबीए के बाद इसका काफी महत्व होता है। एमबीए और पीजी डिप्लोमा के अलावा आप एमएस कोर्स भी कर सकते हैं और मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ले सकते हैं। 2 वर्ष के इस कोर्स को किसी भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन है कि आप कितनी तत्परता से इन कोर्सज को सीखते हैं और कितनी स्वीड के साथ अपने करियर में अपनाते हैं। अगर आप सावधानीपूर्वक और फोकस तरीके से इसे करते हैं, तो ना केवल एंट्रेंप्रेनोरशिप में, बल्कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्प्लानि चैन मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भी अपने झंडे गाड़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, कंसलटेंसी, एडिपेशन, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, आईटी, इंड्योरेंस, ऑनलाइन मार्केटिंग, मैनुफैक्चरिंग इत्यादि इंडस्ट्रीज आपको हाथों हाथ ले सकती हैं।



इन तरीकों से भी आप जुड़ सकते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री से

इसके बारे में तो हर कोई जानता है। एक मेकअप आर्टिस्ट पार्टी वियर मेकअप से लेकर ब्राइडल, फोटोशूट, मीडिया मेकअप आदि करता है। इनका मुख्य काम कॉस्मेटिक्स का सही तरह से एप्लीकेशन करना होता है और इन्हें कलर्स व शेड्स की काफी अच्छी जानकारी होती है। बतौर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप सैलून, फिल्म, थिएटर, मॉडलिंग एजेंसी या फैशन डिजाइनर्स आदि के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं।

जब भी ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाने की बात होती है तो सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट बनने का ही ख्याल आता है। यकीनन यह करियर ऑप्शन हर किसी के मन को लुभाता है और आजकल तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी बतौर मेकअप आर्टिस्ट बनकर अच्छा खासा पैसा और नाम कमा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बनकर ही अपना करियर संवारे। अगर आप भी खुद को खूबसूरती की इस दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अन्य कई राहों को चुन सकते हैं। तो चलिए आप हम आपको इनमें से कुछ के बारे में बताते हैं-

मेकअप आर्टिस्ट

इसके बारे में तो हर कोई जानता है। एक मेकअप आर्टिस्ट पार्टी वियर मेकअप से लेकर ब्राइडल, फोटोशूट, मीडिया मेकअप आदि करता है। इनका मुख्य काम कॉस्मेटिक्स का सही तरह से एप्लीकेशन करना होता है और इन्हें कलर्स व शेड्स की काफी अच्छी जानकारी होती है। बतौर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप सैलून, फिल्म, थिएटर, मॉडलिंग एजेंसी या फैशन डिजाइनर्स आदि के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं।

ब्यूटी ब्लॉगर

अगर आप अपने टैलेंट व स्किल को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो इसमें इंटरनेट की मदद लें। आप बतौर ब्यूटी ब्लॉगर खुद को स्थापित कर सकते हैं। आप लेखन या वीडियो के जरिए अपने स्किल्स को लोगों के साथ बांट सकते हैं। अगर आप सच में मेकअप व ब्यूटी केयर की गहरी समझ रखते हैं तो यकीनन लोग आपको काफी पसंद करेंगे। आप अपने ब्लॉग में किसी मेकअप प्रॉडक्ट का रिव्यू करने से लेकर ब्यूटी व मेकअप करने की तकनीक, मेकअप ट्यूटोरियल, ब्यूटी टिप्स व टेंड के बारे में बता सकते हैं। बस आप अपना ब्लॉग या चैनल शुरू करें और अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटें। बतौर ब्यूटी ब्लॉगर आप खुद को काफी फेमस भी कर सकते हैं।

हेयर स्टाइलिस्ट

कभी भी मेकअप तभी अच्छा लगता है, जब हेयरस्टाइलिंग भी अच्छी हो। जहाँ कुछ समय पहले तक मेकअप आर्टिस्ट ही हेयर स्टाइलिंग करते थे, वहीं अब अलग से प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट की डिमांड होने लगी है। हेयर स्टाइलिस्ट बालों को कटिंग, ट्रिमिंग, स्टाइलिंग और अन्य तरीकों से आपको एकदम परफेक्ट लुक देते हैं। बतौर हेयरस्टाइलिस्ट आप एक्टर, थिएटर प्रॉडक्शन, टेलीविजन सेट्स या मेकअप आर्टिस्ट के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं।

नेल टेक्नीशियन

पिछले कुछ समय से नेल आर्ट का फ्रेज काफी बढ़ गया है। आजकल नाखूनों को एक केनवास के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर आप अपनी क्रिएटिविटी को आसानी से उकेर सकते हैं। प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन की मार्केट में अलग से डिमांड है। यह नाखूनों पर बेहद खूबसूरत नेल डिजाइन्स बनाते हैं। बतौर नेल टेक्नीशियन आप खुद का नेल सैलून खोल सकते हैं या फिर अन्य सैलून, स्पा या रिसॉर्ट आदि में काम कर सकते हैं।

इन प्रश्नों की मदद से आप किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं

अक्सर हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के विषय में जब जानना चाहते हैं तो हम उससे कुछ सवाल पूछते हैं। उन सवालों के आधार पर हम ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। आइए जानते हैं उन सैम्यल प्रश्नों के विषय में जिन्हें आधार बनाकर किसी की पर्सनैलिटी के विषय में पता लगाया जा सकता है।

आपका रोल मॉडल कौन है?

यह प्रश्न आपको किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं और उद्देश्यों के बारे में बहुत कुछ बताएगा। आप लोगों की लिस्ट पेश करके पूछ सकते हैं कि आप किस व्यक्ति को सबसे अधिक सराहना करते हैं और आपका रोल मॉडल कौन है। प्रत्येक विकल्प किसी व्यक्ति के लिए एक निश्चित प्रवृत्ति या प्राथमिकता की ओर निर्देशित कर सकता है। इस प्रश्न के जरिए किसी की पर्सनैलिटी का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

आपको सबसे बेहतर कौन जानता है?

व्यक्ति के खुलेपन और घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो यह प्रश्न उस व्यक्ति के बारे में यह बताएगा। यदि उनकी अपनी मां उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानती है, तो आप एक अंतर्मुखी के साथ बात कर रहे हैं। यदि कोई कहता है कि उन्हें अपनी बहन और एक दोस्त सबसे अच्छी तरह से

जानते हैं, तो आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो मतभेदों और असहमति के बावजूद लोगों को जानने और उनके साथ संबंध के लिए हमेशा तैयार रहता है।

आपने अपनी सबसे बड़ी असफलता से क्या सीखा?

यह प्रश्न बताता है कि क्या कोई व्यक्ति क्रिएटिव तरीके से अपनी असफलता से निपटता है। इन प्रश्न के उत्तर के बाद आप जान सकते हैं कि व्यक्ति पॉजिटिव पर्सनैलिटी का है या नेगेटिव पर्सनैलिटी का।

अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं?

यह आपके दिखाएगा कि एक व्यक्ति समझदार और कैसे निपटता है और काम में बाधा आने पर उनके कार्य करने की संभावना कैसे होती है। पर्सनैलिटी जानने के लिए यह सबसे बेहतर तरीका हो सकता है।

वह कौन सा तरीका है जो आपको शांत करने में मदद करता है?

किसी के व्यवहार के बारे में जानना है तो ये जरूर जानिए कि व्यक्ति विषम परिस्थितियों में खुद को शांत कैसे रखता है। जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में खुद को शांत रख सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है।



रुपया गिरावट पर बंद



मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मंगलवार को 14 पैसे की गिरावट के साथ ही 82.89 पर बंद हुआ। इससे पहले रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह पैसे गिरकर 82.81 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुख और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के कारण रुपया कमजोर हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से डॉलर की मजबूती और विदेशी कोषों की बिकवाली के कारण रुपये पर दबाव है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.80 पर खुला और फिर 82.81 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले छह पैसे की गिरावट बताता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार को शुरू हो रही है, जिसके नीतिगत फैसले की घोषणा गुरुवार को की जाएगी। कारोबारियों को इस घोषणा का भी इंतजार है। रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले छह पैसे बढ़कर 82.75 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.28 प्रतिशत बढ़कर 102.33 पर पहुंच गया।

जुलाई में मुद्रास्फीति बढ़कर हो सकती है 6.7 फीसदी

मुंबई। खाने की वस्तुओं की कीमतों में तेजी से जुलाई महीने की खुदरा महंगाई दर में तेज वृद्धि हो सकती है और यह पिछले महीने के मुकाबले 1.90 प्रतिशत बढ़कर 6.7 प्रतिशत तक जा सकती है। एक विदेशी बैंक के अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है। डॉलर के मुकाबले डॉलर के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा कि जुलाई महीने की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो सकती है जो जून में 4.8 प्रतिशत थी। बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कोशिक दास की अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय की यह रिपोर्ट जुलाई महीने में आने वाली मुद्रास्फीति के आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले आई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार से शुरू हो गई है और मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा 10 अगस्त को की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को इस बार भी यथावत रख सकता है। पिछली दो समीक्षा में नीतिगत दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण टमाटर और प्याज की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी है। साथ ही चावल के दाम में भी बढ़े हैं। जरूरी 22 खाद्य वस्तुओं के दैनिक दाम 12.3 प्रतिशत बढ़े हैं जबकि जून में इसमें औसतन 2.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। प्रमुख सखियों में टमाटर के दाम जून में 236.1 प्रतिशत बढ़े जबकि जून में इसमें 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वहीं प्याज की कीमत 4.2 प्रतिशत के मुकाबले 15.8 बढ़ी। आलू की कीमत जून के 5.7 प्रतिशत के मुकाबले जुलाई में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एयर इंडिया के बेड़े में जल्द शामिल होंगे 9350 और बी737 मैक्स विमान

नई दिल्ली। एयर इंडिया के बेड़े में बहुत जल्द ए350 और बी737 मैक्स विमान शामिल होने वाले हैं। मूल रूप से ये विमान चीन और रूसी वाहकों के लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों (रूस और चीन) पर बैन ने टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइन के लिए इन विमानों की डिलीवरी की समयसीमा में तेजी ला दी है। ये विमान सितंबर से दिसंबर के बीच एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि एयर इंडिया ने फरवरी में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होने वाले एयरबस ए350 विमानों का पहला बैच मूल रूप से एअरओपलोट के लिए था। हालांकि, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण इन्हें डिलीवर नहीं किया जा सका। इसी तरह, चीनी वाहक और पड़ोसियों द्वारा ऑर्डर किए गए 55 बोइंग 737 मैक्स विमानों को स्थानीय सरकार के प्रतिबंध के कारण रिजर्वेक्ट किया गया है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि बी737 मैक्स की डिलीवरी अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में होने का अनुमान है, इसके बाद ए350 की डिलीवरी होगी।

स्टरलाइट को मिला 250 करोड़ का ऑर्डर

नई दिल्ली। दुनिया में 5जी ग्राहकों की संख्या बढ़ने की वजह से ऑप्टिकल और डिजिटल सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अपने मुनाफे को केश कराना चाहती है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी का कामाना है कि आने वाले समय में फाइबर की मांग मजबूत बनी रहेगी। हाल ही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी से समझौता किया है। इसमें कंपनी उस पीएसयू के लिए डाटा सेंटर फेसिलिटी के डिजाइनिंग, बिल्डिंग, कमिश्निंग और मॉन्टोरिंग का काम करेगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को मिला यह ऑर्डर 250 करोड़ रुपए का है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का 3 साल के लिए कामकाज देखेगी। 30 जून 2023 तक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का ऑर्डर बुक 10938 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस ऑर्डर के मिलने के बाद से ही कंपनी के शेयरों में करीब 8 फीसदी का उछाल देखने को मिला। सोमवार को शेयर बाजार के टॉप गेनर्स में शामिल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर 8 फीसदी की तेजी पर 164 के लेवल पर पहुंच गए थे।

ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी मीशो मुनाफे में आई

नई दिल्ली। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी मीशो मुनाफे में आ गई है। सोपटैक के निवेश वाली इस कंपनी ने कहा कि ऑर्डर की संख्या और राजस्व में इजाफे तथा खर्चों में कटौती के कारण जुलाई में उसे कर पक्षत मुनाफा हुआ है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी एचए संस्थापक विदित अत्रेय ने कहा कि हम हर तरह का सामान बेचने वाले भारत के पहले ई-कॉमर्स



प्लेटफॉर्म हैं, जो मुनाफे में आए हैं। हम लगातार वृद्धि के लिए सभी को ई-कॉमर्स मुहैया कराने के लिए और भारत के हर हिस्से की असली सभावना सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोपटैक, मेटा प्लेटफॉर्म और प्रोसस जैसे दिग्गजों के निवेश वाली बेंगलूरु की कंपनी मीशो का जुलाई में हुआ मामूली मुनाफा सभी खंडों और श्रेणियों से आया है, जिनमें ई-सॉफ्ट भी शामिल हैं। कंपनी ने कर के बाद मुनाफे का सही आंकड़ा बताने से इनकार कर दिया मगर यह 10 करोड़ रुपए से कम है। मीशो के मुख्य वित्त अधिकारी धीरेश बंसल ने कहा कि पिछले 12 महीनों में मीशो का कारोबार शानदार रहा है। ऑर्डरों की संख्या 43 प्रतिशत बढ़ गई है और 1 अरब से भी अधिक ऑर्डर आए हैं। बंसल ने कहा कि पिछले 12 महीनों में कंपनी का राजस्व 5 प्रतिशत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि कारोबार में भारी बढ़ोतरी और इससे अधिक कमाई होने से राजस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनवरी से जून 2023 के दौरान मीशो की आय 40 करोड़ डॉलर थी। इस साल के अंत तक हमें 80 करोड़ डॉलर से अधिक सालाना राजस्व का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 तक 10,000 करोड़ रुपए राजस्व का कंपनी का लक्ष्य है।

शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद

मुंबई (एजेंसी)। शेयर बाजार मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले-जुले संकेतों के बीच ही बाजार गिरावट पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आईटी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी रही। वहीं दूसरी ओर धातु और उपभोक्ता क्षेत्र के शेयर में गिरावट रही।

कारोबारियों को अब इस सप्ताह आने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार है। इसके अलावा विदेशी कोषों की बिकवाली जारी रहने से भी बाजार पर विपरीत दबाव आया।

दिन भर के कारोबार के बाद तीसरे शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 106.98 अंक करीब 0.16 फीसदी नीचे आकर 65,846.50 अंक पर बंद हुआ जबकि कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 66,057.53 तक जाने के बाद 65,752.63 तक गिरा।

दूसरी तरफ पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 26.45 अंक तकरीबन 0.13 फीसदी टूटकर बंद हुआ। निफ्टी दिन के अंत में 19,570.85 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,634.40 की ऊंचाई तक जाने के बाद 19,533.10 तक गिरा।

आज के कारोबार में सेंसेक्स के शेयरों में 10 शेयर लाभ पर बंद हुए। टेक महिंद्रा, विप्रो, बजाज फाइनेंस, एस्बीआई और एक्सिस बैंक सेंसेक्स



के सबसे अधिक लाभ वाले पांच शेयर रहे। सबसे ज्यादा लाभ 1.82 फीसदी टेक महिंद्रा के शेयरों को हुआ।

वहीं, दूसरी तरफ सेंसेक्स के शेयरों में 20 शेयर नुकसान पर बंद हुए। पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक और सन फार्मा सेंसेक्स के सबसे अधिक पांच नुकसान वाले शेयर रहे। सबसे ज्यादा नुकसान पावर ग्रिड के शेयरों को हुआ। इसके शेयर करीब 2.62 फीसदी तक टूटे। वहीं आज सुबह बाजार

हल्की बढ़त पर खुला। सेंसेक्स 192 अंक ऊपर 65913 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी 20 अंक ऊपर 19617 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बावजूद महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी से बाजार बढ़ते से शुरु हुआ हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी जारी रहने से बाजार जोरदार बढ़त नहीं दर्ज कर सका था और समय के बाद इसमें गिरावट आने लगी।

टमाटर की बढ़ती कीमत का असर, महंगा हुआ शाकाहारी खाना

- वित्त वर्ष 2023-24 में यह पहली बार है जब कीमतें साल-दर-साल के नजरिये से भी महंगी हुईं

मुंबई (एजेंसी)। टमाटर की बढ़ती कीमतों के कारण जून की तुलना में जुलाई में शाकाहारी थाली तैयार करना 34 प्रतिशत महंगा हो गया। एक रेटिंग (साख निर्धारक) एजेंसी की इकाई ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। आगस्त के लिए क्रिसिल की 'रोटी चावल दर' रिपोर्ट में कहा गया है कि मांसाहारी थाली पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा है और इसे तैयार करने की कीमत केवल 13 प्रतिशत बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि थालियों की महंगाई काफी हद तक टमाटर की कीमतों में 23.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण हुई है। टमाटर का दाम जुलाई में 110 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जबकि जून में यह 33 रुपए किलो था। क्रिसिल ने कहा कि घर पर थाली तैयार करने की औसत लागत की

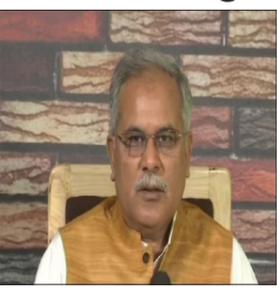
गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में प्रचलित लागत वस्तुओं की कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें कहा गया है कि थाली की कीमत के महंगा होने का यह लगातार तीसरा महीना है। इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में यह पहली बार है जब कीमतें साल-दर-साल के नजरिये से भी महंगी हो गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मासिक आधार पर प्याज और आलू की कीमतें क्रमशः 16 प्रतिशत और नौ प्रतिशत बढ़ीं, जिससे लागत में और वृद्धि हुई। जून की तुलना में जुलाई में मिर्च की कीमतें 69 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन चूक भोजन तैयार करने के लिए इसकी जरूरत थोड़ी कम रहती है, इसलिए थाली तैयार करने पर इसका प्रभाव सीमित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मांसाहारी थाली के लिए थाली की कीमत में कम मात्रा में बढ़ोतरी का कारण ब्रायलर चिकन की कीमत में 3 से 5 प्रतिशत की गिरावट से आना है, जिसका थाली की लागत में लगभग आधा हिस्सा होता है।

बघेल का सीतारमण को पत्र, 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का आग्रह

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का अनुरोध किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा है तथा जीएसटी प्राधिकरण द्वारा 'पेहन गैर' के रूप में कमेर और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा हाल ही में



12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों को कठिनाई होगी,

क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से यह भी संभव है कि कई गरीब प्रतिभावान छात्रों को अपने मूल निवास स्थान वापस लौटने के लिए विवश होना पड़े। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इस विषय पर केंद्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप कर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

पेट्रोल और डीजल यूपी-एमपी में महंगा, राजस्थान में गिरे दाम

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत मामूली तेजी दिख रही है। डब्ल्यूआईआई कूड 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 82.35 डॉलर प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं ब्रेट कूड 0.38 डॉलर बढ़कर 85.72 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। भारत में हर सुबह 6 बजे इंधन के दामों में संशोधन किया जाता है। जून 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता था। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 37 और डीजल 36 पैसे महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 44 और डीजल 41 पैसे महंगा हुआ है। दूसरी ओर राजस्थान में पेट्रोल 35 और डीजल 32 पैसे सस्ता हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल 32 और डीजल 28 गिरकर बिक रहा है। महाराष्ट्र में भी वाहन इंधन की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपए और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपए और डीजल 94.33 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में पेट्रोल 96.92 रुपए और डीजल 89.82 रुपए प्रति लीटर हो गया है। गाजियाबाद में 97.91 रुपए और डीजल 89.75 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 96.43 रुपए और डीजल 89.66 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

खस्ता होती जा रही है चीन की इकॉनामी, तरह-तरह की जताई जा रही आशंका

- इंगन को छोड़कर भाग रहे विदेशी निवेशक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनामी चीन की हालत खस्ता होती-दिखाई देने लगी है। उसके इकॉनामिक ग्रोथ को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसका तनाव भी लगातार बना हुआ है। इससे विदेशी निवेशकों ने चीन से किनारा करना शुरू कर दिया है। गोल्डमैन सैच के मुताबिक इस साल के पहले छह महीनों में जापान के शेयरों में विदेशी निवेश चीन के मुकाबले आगे निकल गया है। साल 2017 के बाद यह पहला मौका है जब ऐसा हुआ है।

जुलाई में भी यह बिकवाली जारी है जबकि चीन और हॉंग कॉन्ग के बाजारों में तेजी आई है। जानकारों का कहना है कि जापान में मॉनीटरी पॉलिसी सामान्य हो रही है। इससे येन की कीमत में अचानक तेजी आने की संभावना नहीं है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब एक बार फिर चीन को छोड़कर जापान का रुख कर रहे हैं। एशिया पर फोकस फंड एलायंस औरिएटल इनकम के पास एक अरब डॉलर के एसेट्स हैं। यह कंपनी चीन से पैसा निकालकर जापान में लगा रही है। जून के अंत में फंड में जापान का वेटेज 40 फीसदी था जो चीन में कंपनी के निवेश से पांच गुना ज्यादा है। एशिया पैसिफिक में जापान के शेयर मार्केट चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन की

इकॉनामी सुस्त होती जा रही है और उसके हालात देखकर लोगों को जापान की याद आ रही है। एक जमाने में जापान की इकॉनामी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और माना जा रहा था कि वह अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन 1990 के दशक में जापान की इकॉनामी में ठहराव आ गया। हालांकि तब तक जापान की हाई-इनकम वाले देशों की श्रेणी में पहुंच चुका था और अमेरिका के लेवल के करीब था। आज चीन के हालात भी कमोबेश वैसे ही हैं। अंतर इतना है कि चीन मिडल इनकम पाइंट से थोड़ा ही ऊपर पहुंचा है। चीन के नीति-निर्माताओं को उम्मीद थी कि चीन जल्दी ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन हाल फिलहाल यह संभव नहीं दिखता है।

क्यूआईए ने अडाणी ग्रीन एनर्जी में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी

मुंबई (एजेंसी)। कतर के सरकारी संपत्ति कोष कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए) ने अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में लगभग 50 करोड़ डॉलर में 2.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी मिली है। अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के बाद समूह की कंपनी में पर्यावरण, सामाजिक और कंपनी संचालन केन्द्र (ईएससी) फंड का यह दूसरा निवेश है। इससे पहले, 2020 में, क्यूआईए ने अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की अनुष्णगी कंपनी अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। शेयर बाजार में उल्लब्ध आंकड़ों के अनुसार, अडाणी ग्रीन एनर्जी की प्रवर्तक इकाई इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के कंपनी में 4,131 करोड़ रुपए में 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। यह सौदा खुले बाजार में लेन-देन के जरिये

हुआ। प्रवर्तक इकाई ने 4,48,82,500 शेयर हिस्सेदारी प्राधिकरण (क्यूआईए) ने अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में लगभग 50 करोड़ डॉलर में 2.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी मिली है। अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के बाद समूह की कंपनी में पर्यावरण, सामाजिक और कंपनी संचालन केन्द्र (ईएससी) फंड का यह दूसरा निवेश है। इससे पहले, 2020 में, क्यूआईए ने अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की अनुष्णगी कंपनी अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। शेयर बाजार में उल्लब्ध आंकड़ों के अनुसार, अडाणी ग्रीन एनर्जी की प्रवर्तक इकाई इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के कंपनी में 4,131 करोड़ रुपए में 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। यह सौदा खुले बाजार में लेन-देन के जरिये

अब दुनिया में चलेगा भारत का सिक्का, यूएस-जापान-कनाडा सब छूटे पीछे

- विश्व बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने दी इंडियन इकोनॉमी की दुहाई

नयी दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। अब दुनिया में केवल भारत का ही सिक्का चलने वाला है। क्यों? कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। विश्व बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने इंडियन इकोनॉमी की दुहाई देते हुए इसकी रफ्तार बेहतर बताई है। जानकार बताते हैं कि आने वाला समय जहां अमेरिका, जापान, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों के लिए परेशानी वाला साबित हो सकता है, लेकिन भारत के लिए ये शानदार रहने वाला है। जबकि दुनिया के कई देशों में लोग फाइनैशियल स्ट्रगल से जूझ रहे होंगे, तो ऐसे में भारत समेत कुछ देश और अमीर होते नजर आने वाले हैं। वर्तमान समय में दुनिया में जो हालात हैं, उनके बीच दो ऐसे फैक्टर हैं, जो आने वाले समय में अमेरिका, कनाडा, जापान और अन्य यूरोपीय देशों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाले हैं। वहीं भारत, वियतनाम और चीन जैसे देशों के लिए फायदेमंद रहेंगे। दरअसल, एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्ट

यानी पश्चिम लगातार बूढ़ा होता जा रहा है। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में कामकाजी या पेशावर की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। इन देशों में कामकाजी आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है। वहीं यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई देश रहत महसूस कर रहे हैं। भारत और वियतनाम जैसे देशों में कामकाजी आबादी का ज्यादातर हिस्सा यंग है। अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देशों में कर्मचारियों की उम्र के आंकड़े तस्वीर साफ कर देते हैं। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका (यूएस) के एक तिहाई (37.3 फीसदी) से भी अधिक वर्कफोर्स 50 वर्ष और उससे अधिक आयु का है, ऐसे में कर्मचारियों का ये आंकड़ा लगभग 16.1 मिलियन होता है। वहीं लगभग 15 फीसदी वर्कफोर्स या 614 मिलियन कर्मचारी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। अगर जापान की बात करें तो वहां भी बूढ़ी होती आबादी बड़ी समस्या बनकर उभरी है और सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जापान में जन्मदं में हो रही गिरावट और

सोने और चांदी की कीमत में गिरावट



नयी दिल्ली (एजेंसी)। सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार के बाद मंगलवार को भी गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अगले फैसले को लेकर अनिश्चितता के चलते है। मंगलवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव कॉमिक्स पर 0.16 फीसदी की गिरावट के साथ 23.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 0.06 फीसदी की बढ़त के साथ 23.15 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं सोने के वैश्विक भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह कॉमिक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.14 फीसदी या 2.70 डॉलर की गिरावट के साथ 1967.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा।

वहीं सोने का वैश्विक हाजिर भाव 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 1932.97 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। सोने के साथ ही मंगलवार सुबह चांदी की वायदा कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर 5 सितंबर 2023 की डिलीवरी वाली चांदी मंगलवार सुबह 88 रुपए की गिरावट के साथ 71,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा। सोने की घरेलू वायदा कीमतों में मंगलवार सुबह गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्राती कारोबार में 5 अक्टूबर, 2023 की डिलीवरी वाला सोना 30 रुपए की गिरावट के साथ 59,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया।



गुजरात सरकार के साथ 1113 करोड़ के एमओयू, 4500 लोगों को मिलेगा रोजगार

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में गुजरात को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के रूप में स्थापित करने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की दसवीं श्रृंखला जनवरी-2024 में आयोजित होने वाली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इस समिट को सफल बनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध आयोजन शुरू किए हैं। यह वाइब्रेंट समिट देश-विदेश के निवेशकों तथा उद्यमियों के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनी है। इस संदर्भ में वाइब्रेंट गुजरात समिट-2024 के पूर्वार्ध में राज्य सरकार ने विभिन्न उद्योगों के

साथ अभी से ही एमओयू करने का उपक्रम प्रारंभ किया है। इस उपक्रम के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक गृहों द्वारा राज्य में नए उद्योग शुरू करने के लिए मंगलवार, 8 अगस्त को गांधीनगर में 1113 करोड़ रुपए के कुल निवेश की तीन कड़ियों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 3874 करोड़ रुपए के निवेश के 14 एमओयू हुए हैं। इन उद्योगों के शुरू होने से आने वाले दिनों में कुल मिलाकर साढ़े नौ हजार से अधिक संभावित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तदनुसार, टेक्स्टाइल क्षेत्र

में 2100, इंजीनियरिंग क्षेत्र में 700, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 500 तथा केमिकल क्षेत्र में 308 5 संभावित रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में सरलता से उद्योग शुरू किए जा सकने योग्य प्रो-एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना की। मंगलवार 8 अगस्त को हुए एमओयू के अनुसार साणंद, डेसर-चडोदरा, पिपोदरा-सूरत सहित बलसाड के डुंगरी में 2024-25-26 तक इन उद्योगों को शुरू करने की योजना है। इस एमओयू के अनुसार, वंडर स्पेसटैलिमिटेड गुजरात में अपना प्रथम प्रोजेक्ट डेसर

तहसील के तुलसी गाँव में 550 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू करेगी। इसके अलावा, हमी वेवेलन प्राइवेट लिमिटेड सूरत की मांगरोळ तहसील के पिपोदरा में विस्कोस स्टेपल यार्न और पॉलिस्टर स्टेपल यार्न का प्रोजेक्ट 114 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू करने वाली है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 300 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, मोरारि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बलसाड ज़िले के डुंगरी में 149 करोड़ रुपए के निवेश से इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेगी और इससे लगभग 3500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

लोकसभा चुनाव 2023 से पहले गुजरात की राजनीति में एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेडियापाडा से विधायक चैतर वसावा को लोकसभा चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो आप के चैतर वसावा का भाजपा सांसद मनसुख वसावा से मुकाबला होना तय है। केजरीवाल की मंजूरी मिलने के बाद चैतर वसावा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप विधायक चैतर वसावा और भाजपा सांसद मनसुख वसावा

आप विधायक चैतर वसावा लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, भाजपा के मनसुख वसावा से करेंगे मुकाबला

अहमदाबाद। लोकसभा चुनाव 2023 से पहले गुजरात की राजनीति में एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेडियापाडा से विधायक चैतर वसावा को लोकसभा चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो आप के चैतर वसावा का भाजपा सांसद मनसुख वसावा से मुकाबला होना तय है। केजरीवाल की मंजूरी मिलने के बाद चैतर वसावा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप विधायक चैतर वसावा और भाजपा सांसद मनसुख वसावा

के बीच कई बार मतभेद हुए हैं। चैतर वसावा सार्वजनिक बहस के लिए मनसुख वसावा को चुनौती दे चुके हैं। मनसुख वसावा ने चुनौती स्वीकार करते हुए चैतर वसावा को सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि बाद में नर्मदा में होनेवाली सार्वजनिक बहस स्थगित कर दी गई थी। बता दें कि सोमवार को आप के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही गढ़वी ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा गुजरात की सभी 26 सीटें नहीं जीत पाएगी। इसुदान गढ़वी ने कहा था पहले कांग्रेस और आप गठबंधन करेगी और

सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनाने के बाद मैदान में उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आप से गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमांड करेगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रमुख जगदीश ठाकोर ने कहा कि आप के साथ गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अगर केन्द्रीय नेतृत्व ने कोई फैसला किया है तो उसकी हमें जानकारी नहीं है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अर्जुन मोहवाडिया ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी हाईकमांड के इस संदर्भ में फैसले की गुजरात कांग्रेस को जानकारी नहीं है।

2025 तक चार लाख वनवासी गांवों में भारतीय संस्कार और संस्कृति पहुंचाना लक्ष्य



सूरत भूमि, सूरत। भारतीय संस्कार, संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लक्ष्य के साथ श्रीहरि सत्यंग समिति द्वारा आयोजित फतेहाबाद रोड स्थित होटल रिच ग्रैंड में वनवासियों के उत्थान को समर्पित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें देश भर के 28 शहरों सहित नेपाल के तीन चैटर के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ समिति के राष्ट्रीय संरक्षक एसएन कावरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए महेश

मित्तल, प्रकल्प प्रभारी मानवेन्द्र, महामंत्री अनिल मानसिंहका ने भारत माता व स्वामी विवेकानन्द की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए महेश मित्तल ने बताया कि समिति द्वारा देश के 55 हजार गांवों में वनवासी कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 2025 तक देश के चार लाख वनवासी गांव तक भारतीय संस्कार और संस्कृति को पहुंचाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना लक्ष्य है। इसके लिए संस्कार केन्द्र व रथ योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर 28 शहरों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उल्लेख्य कार्य करने वाले शहरों को

स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। अतिथियों का स्वागत संरक्षक भगवान दास बंसल व धन्यवाद ज्ञापन संजय गोयल ने दिया। संचालन रूचि अग्रवाल ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झलकी भारतीय कला और संस्कृति - आयोजन में श्रीकृष्ण, रुक्मिणी और सत्यभामा की श्रीकृष्ण को तराजू में तोलने की कथा के मंचन ने सभी अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आगरा महिला समिति की सदस्याओं द्वारा कथा के मंचन ने संदेश दिया कि भगवान को धन दौलत नहीं बल्कि भाव और श्रद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है। वहीं सदस्याओं द्वारा प्रस्तुत महारास ने ब्रज की कला और संस्कृति से अवगत कराया। वनवासी कथाकारों द्वारा भवन प्रस्तुत किए गए।

आप के गठबंधन के दावे पर गुजरात कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा

अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी (आप) के उस दावे से गुजरात कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा लिया है, जिसमें उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन का दावा किया था। इतना ही कांग्रेस ने गुजरात की जनता को सतर्क करते हुए ऐसे बयानों से दूर रहने की अपील की है। बता दें कि सोमवार को आप के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही दावा किया था कि आप और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा गुजरात की सभी 26 सीटें जीत नहीं पाएगी।

आप के गुजरात प्रमुख इसुदान गढ़वी के इस बयान की प्रदेश कांग्रेस ने हवा निकाल दी है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने राज्य की जनता को सतर्क करते हुए ऐसे बयानबाजी से दूर रहने की अपील की है। ऐसी बयानबाजी से राजनीति नहीं होती। उन्होंने कहा कि बगैर सोचे समझे दिए ऐसे बयान का कोई महत्व नहीं है। मनीष दोशी ने कहा कि टिकट वितरण का अधिकार प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं होता। गठबंधन का भी ऐलान पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इसलिए गुजरात के लोगों को ऐसे बयानों से दूर रहने की गुजरात कांग्रेस की अपील है। गौरतलब है

आप के गुजरात प्रमुख इसुदान गढ़वी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ बना गठबंधन जिसका नाम इंडिया वह गुजरात में भी लागू होता है। इंडिया गठबंधन से भाजपा बुरी तरह डर गई है और उसे आभास हो गया है कि इंडिया उसे लोकसभा चुनाव 2024 में हरा देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के नेता इंडिया के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। गढ़वी ने कहा था कि गुजरात में सीटों का बंटवारा कर कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर सीटों का सही ढंग से बंटवारा हुआ तो भाजपा में गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटें जीत नहीं पाएगी।

लखदातार सेवा समिति द्वारा विशाल श्री श्याम अखाड़ा का आयोजन 15 अगस्त को

सूरत भूमि, सूरत। लखदातार सेवा समिति द्वारा विशाल श्री श्याम अखाड़ा का आयोजन 15 अगस्त, मंगलवार को वीआईपी रोड स्थित श्याम विष्णु अर्पाटमेंट में किया जायेगा। समिति के संरक्षक विजय कुमार तोदी ने बताया कि इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य एवं आलौकिक दरबार सजाया जायेगा। श्रृंगारित दरबार के समक्ष दोपहर एक बजे से अर्धरात्रि तक प्रज्वलित की जाएगी। इसके पश्चात् विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जायेगा। भजन संध्या में सूरत के लोक लाडले कलाकारों द्वारा भजनों एवं धमाल की प्रस्तुति दी जाएगी। श्री श्याम अखाड़ा के आयोजक पवन मुरारका ने बताया कि आयोजन के दौरान अर्धरात्रि, पुष्प-वर्षा, इत्र-फुहार, भव्य दरबार आदि भक्तों के आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे। आयोजन में सूरत सहित आस-पास के शहरों से भी अनेकों श्याम भक्त उपस्थित रहेंगे।



मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज तापी सहित 14 जिलों में मनाया जाएगा 'विश्व आदिवासी दिवस'

गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में तापी के गुणसदा सहित 14 जिलों में विभिन्न मंत्रियों की उपस्थिति में 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाया जाएगा। राज्य सरकार गुजरात में रहने वाले लगभग 89.17 लाख आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक, स्वास्थ्य-सुख और सामाजिक सहित सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। गुजरात में अंबाजी से लेकर उमरगाम तक की पूर्वी पट्टी के 14 जिलों में लगभग 29 लाख से अधिक आदिवासी समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक उत्कर्ष के लिए विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक 72,719 लाख रुपए की सहायता दी गई है। वहीं, पूरे राज्य के आदिवासियों के 1952 स्कूलों व छात्रवासियों में लगभग 2.16 लाख छात्र निवासी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व

और आदिवासी विकास मंत्री डॉ. कुबेर डिंडोर एवं राज्य मंत्री कुंवरजी हळपति के मार्गदर्शन में चालू वर्ष 2023-24 में आदिवासी विकास विभाग के बजट में कुल 3,410 करोड़ रुपए के प्रावधान में सर्वाधिक 2,294.29 करोड़ की राशि केवल शैक्षणिक उत्कर्ष के लिए ही आवंटित की गई है, जो सरकार की आदिवासी शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व के परिणामस्वरूप अंबाजी से उमरगाम तक की पूर्वी पट्टी के 14 जिलों के आदिवासी बहुल शहरों और गांवों में विकास की एक नई परिभाषा लिखी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए 'वन वंश कल्याण योजना-2' के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से

2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए की बजटीय घोषणा भी की गई है। वैश्विक स्तर पर आदिवासियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (यूएन डीईएसए) की ओर से प्रति वर्ष 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए वर्ष 2023 में 'आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा' थीम निर्धारित की गई है। वर्तमान में आदिवासी छात्रों को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 08 योजनाएं कार्यरत हैं। इन योजनाओं में केंद्र सरकार प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 1,02,797 छात्रों को, विद्या साधना योजना के तहत कक्षा 9वीं के 38,237 छात्रों को साइकिल सहायता, 1,8

5,638 को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, चिकित्सा और इंजीनियरिंग संकाय के 1,550 छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक उपकरण सहायता, आईटीआई के 10,8 67 छात्रों को छात्रवृत्ति तथा 13,07,234 छात्रों को गणवेश सहायता सहित कुल 29.83 लाख से अधिक छात्रों को वार्षिक 72,719 लाख रुपए की सहायता विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। गुजरात के 18 फीसदी क्षेत्र के 14 जिलों की 53 तहसीलों के अंतर्गत 5,884 गांवों में आदिवासी समुदाय के नागरिक रहते हैं। इस समुदाय के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक उत्कर्ष के लिए राज्य भर में कार्यरत 44 एकलव्य मॉडल रजिडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) में 14,620 और 43 कन्या साक्षरता निवासी शाला (जीएलआरएस) में 15,121 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नेशनल। सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कंपनी और हरित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन में योगदान देने वाली वारी एनर्जीज लिमिटेड (डब्ल्यूईएल) ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की इंडिटी फंडिंग का एक राउंड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। निवेश के इस दौर का नेतृत्व वैल्यूक्रेस्ट ने किया, जो एक निवेश फर्म है जो सस्टेनेबल और प्रगतिशील उद्यमों पर रणनीतिक फोकस के लिए जानी जाती है। वारी एनर्जी लिमिटेड ने पहले परिवारिक कार्यालयों, एचएनआई आदि सहित निवेशकों के एक समूह से 1040 करोड़ रुपए का प्राथमिक दौर जुटाया था। फंडिंग के मौजूदा दौर का उपयोग 12 गीगावाट की मौजूदा क्षमता के अलावा 6 गीगावाट क्षमता विस्तार

वारी एनर्जीज लिमिटेड ने वैल्यूक्रेस्ट के नेतृत्व में इंडिटी फंडिंग के दूसरे दौर में जुटाए 1000 करोड़ रुपए

के लिए किया जाएगा। अतिरिक्त 6 गीगावाट क्षमता सोलर इन्वॉयर्स और वेफर्स, सेल्स और मॉड्यूल के निर्माण के लिए है। यह इंडिटी निवेश भारत सरकार द्वारा दिए गए 1,923 करोड़ रुपए के पीएलआई की दूसरी किस्त के अतिरिक्त है। कंपनी 5.4 गीगावाट की क्षमता के साथ सोलर सेल्स के निर्माण में बैकवर्ड इंडीग्रेगल को योजना भी बना रही है। अगले 2 वर्षों के भीतर, वारी एनर्जी लिमिटेड के पास 20 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता, 11.4 गीगावाट सेल और 6 गीगावाट वेफर्स विनिर्माण क्षमता होगी। यह विस्तार योजना चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े सौर मॉड्यूल निर्माता के रूप में वारी की स्थिति को और मजबूत करेगी। वारी एनर्जी लिमिटेड का वैल्यूक्रेस्ट के साथ लंबे समय से

जुड़ाव विश्व स्तर पर क्वीन और सस्टेनेबल एनर्जी समाधान प्रदान करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। इस सहयोग ने कंपनी को सौर उत्पाद वितरित करने, अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ाने में सक्षम बनाया है। नवीनतम फंडिंग राउंड नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में एक भागीदार के रूप में वारी एनर्जीज लिमिटेड की क्षमताओं को दर्शाता है। चूंकि कंपनी एक हरित और अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भविष्य योजना चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े सौर मॉड्यूल निर्माता के रूप में वारी की स्थिति को और मजबूत करेगी। वारी एनर्जी लिमिटेड का वैल्यूक्रेस्ट के साथ लंबे समय से

सस्टेनेबल एनर्जी समाधान प्रदान करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। इस सहयोग ने कंपनी को सौर उत्पाद वितरित करने, अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ाने में सक्षम बनाया है। नवीनतम फंडिंग राउंड नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में एक भागीदार के रूप में वारी एनर्जीज लिमिटेड की क्षमताओं को दर्शाता है। चूंकि कंपनी एक हरित और अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भविष्य योजना चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े सौर मॉड्यूल निर्माता के रूप में वारी की स्थिति को और मजबूत करेगी। वारी एनर्जी लिमिटेड का वैल्यूक्रेस्ट के साथ लंबे समय से

2023 की दूसरी तिमाही में रियलमी ने 51 प्रतिशत की मजबूत तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दर्ज की



नई दिल्ली। सबसे भरोसेमंद स्मार्टफोन सेवा प्रदाता, रियलमी ने मशहूर मार्केट रिसर्च फर्म, काउंटरपार्ट के मुताबिक 2023 की दूसरी तिमाही में 51 प्रतिशत की मजबूत तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि हासिल की है। इस अभूतपूर्व वृद्धि ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में रियलमी को मजबूत स्थिति में ला दिया है, और यह 2023 की दूसरी तिमाही के लिए आईडीसी की रैंकिंग के अनुसार सर्वोच्च 10 स्मार्टफोन ब्रांड्स में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन के बाजार में 3 प्रतिशत की साल-दर-साल गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद भी रियलमी की सामरिक पोजिशनिंग और लीप फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट, तथा 10,000 रु. से 15,000 रु. के सेगमेंट में 5जी डिवाइसेज पर उद्योग के फोकस के साथ यह ब्रांड वापस भारतीय स्मार्टफोन बाजार में तीसरे स्थान पर आ गया।

रियलमी को इस अभूतपूर्व वृद्धि में इन्वेस्टी और मांग में सुधार के लिए ब्रांड के सामरिक दृष्टिकोण, जबरदस्त सेल्स प्रमोशन और किफायती मूल्यों में 5जी डिवाइसेज का लॉन्च शामिल है। रियलमी ने इस साल विभिन्न डिवाइसेज के साथ अनेक उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें से कई अपनी-अपनी श्रेणियों में सबसे ज्यादा

बिकने वाली डिवाइसेज रही। रियलमी सी55 की 100,000 से ज्यादा यूनिट पहले दिन की सेल में 5 घंटे में ही बिक गई, जबकि 11 प्रो सीरीज ने अपने प्रारंभिक लॉन्च के दौरान सभी चैनलों पर 200,000 से ज्यादा डिवाइसेज बेचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, और ऑफलाइन पहली सेल की अवधि में इसकी पिछली जनरेशन के मुकाबले 390 प्रतिशत ज्यादा डिवाइसेज बेचीं। इसके अलावा वाचो एफ53 पेंडेंटों पर 10,000 रु. के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, जिसने 90 मिनट में 100,000 यूनिट बेचकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईओटी श्रेणी में रियलमी पेंड 2 ने पहली सेल के दौरान पिछली जनरेशन के मुकाबले 122 प्रतिशत ज्यादा डिवाइसेज बेचीं। इन उपलब्धियों से उम्मीदें बढ़ने और भविष्य में और ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत स्थिति में है।

इसके अलावा, ऑफलाइन चैनलों में रियलमी की मजबूत ऑफलाइन उपस्थिति एवं विस्तार ने ग्राहकों को संलग्नता बढ़ाने और परिवेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर ब्रांड के सामरिक फोकस ने विभिन्न ग्राहकों को पसंद को पूरा करने और अपने उत्पाद आसानी से उपलब्ध बनाने में इसे सफल बनाया। सीमाओं का लाभांतर विस्तार करने और बेहतर डिवाइसेज प्रदान करते हुए रियलमी ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक प्रभावशाली कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उत्पाद की आकर्षक श्रृंखला और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ रियलमी लगातार आगे बढ़ने और भविष्य में और ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत स्थिति में है।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने लॉन्च किया - 'उद्योग प्लस' - एमएसएमई के लिए एक इनोवेटिव वन-स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म

सूरत। आदित्य बिड़ला कैपिटल की ऋण देने वाली सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (एबीएफएल) ने एमएसएमई के लिए एक इनोवेटिव वन-स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह नया बी2बी डिजिटल प्लेटफॉर्म 'उद्योग प्लस' गुजरात के बड़े एमएसएमई क्षेत्र के लिए फाइनेंस संबंधी सॉल्यूशंस को एक व्यापक रूपांतरित करता है। इनमें फाइनेंसिंग, सुरक्षा, निवेश, सलाहकार और मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं। उद्योग प्लस के माध्यम से, एबीएफएल का लक्ष्य गुजरात में एमएसएमई की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रक्रिया अत्यंत आसान और पूरी तरह कागज रहित होगी। इस तरह एमएसएमई को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ऋण देने के परिदृश्य में वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। उद्योग प्लस एक खुला बाजार है जिसे एबीएफएल के मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों द्वारा आदित्य बिड़ला



कैपिटल वेबसाइट के फाइनेंसिंग सेक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। गुजरात में एमएसएमई अब उद्योग प्लस की पूरी तरह से कागज रहित डिजिटल यात्रा के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का व्यावसायिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। असुरक्षित व्यावसायिक ऋणों के अलावा, प्रमोटर्स, मालिकों और कर्मचारियों सहित एमएसएमई का संपूर्ण इको सिस्टम उद्योग प्लस द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठ सकता है, जैसे जरूरत के अनुसार सुरक्षित ऋण, बीमा, निवेश समाधान इत्यादि। इन प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म को ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) और निजी ई-कॉमर्स

वेबसाइटों के माध्यम से सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के साथ एकीकृत किया गया है। आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने एमएसएमई ग्राहकों को अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रणी समाधान प्रदाताओं के साथ भी साझेदारी की है। इन सेवाओं में बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक मुफ्त पहुंच, डिजिटल कॉमर्स, कॉर्पोरेट यात्रा समाधान, जोरो वेलेंस बैंक खाता, अकाउंटिंग, पेरेंट और टेम्स फाइलिंग टूल और विशेष ज्ञान सामग्री केंद्र आदि शामिल हैं। एबीएफएल ने पहले से ही एमएसएमई क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, इसकी कुल ऋण पुस्तिका का लगभग 50 फीसदी हिस्सा बिजनेस लोन से बना है। बाजार में एक स्थापित खिलाड़ी के रूप में, एबीएफएल लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में साल-दर-साल 37 प्रतिशत की वृद्धि हासिल कर रहा है। उद्योग प्लस के लॉन्च के माध्यम से, एबीएफएल का लक्ष्य एमएसएमई के लिए बिजनेस लोन यात्रा को डिजिटल बनाकर क्रेडिट संबंधी सिस्टम को और सरल बनाना है, जिससे आसानी से और तेज गति से ऋण प्रदान किए जा सकें।